राष्ट्रीय हिन्दी दैनिक

स्वतंत्र प्रभात

@swatantraprabhatmedia @swatantramedia RNI.No. UHIN/2012/43078 (epaper.swatantraprabhat.com) @SwatantraPrabhatonline news@swatantraprabhat.com

सीतापुर से प्रकाशित एंव अयोध्या ,प्रयागराज ,मिर्जापर ,गोरखपुर , बरेली ,बुंदेलखंड , उत्तराखंड , देहरादून

सीतापुर, मंगलवार , 09 दिसंबर 2025

वर्ष 14,अंक 236, पृष्ट 04, मूल्यः 01 रुपया

www.swatantraprabhat.com

गाज़ियाबाद , दिल्ली , हरियाणा , चंडीगढ़ , झारखण्ड , बिहार , मध्य प्रदेश ,असम, तेलंगाना आदि जनपदो में प्रसारित

एसडीआरएफ और पुलिस की दमदार कार्रवाईः 36 घंटे बाद पोखरे से बरामद हुआ युवक का शव..03

दुष्कर्म के आरोपी ने कुछ ही घण्टों बाद फंदा लगाकर की आत्महत्या..04

स्वतंत्र प्रभात दैनिक अख़बार तथा ऑनलाइन चैनल से सीधा जुड़ने के लिए संपर्क करें.....
9511151254

वंदे मातरम पर बहस के पीछे बंगाल का चुनाव है... लोकसभा में प्रियंका गांधी ने सरकार को घेरा

स्वतंत्र प्रभात संवाददाता

लोकसभा में वंदे मातरम पर चर्चा में कांग्रेस की नेता और सांसद प्रियंका गांधी ने भी अपनी बात रखी. प्रियंका ने कहा है कि वंदे मातरम देश के कण-कण में है इस पर चर्चा करने की क्या जरूरत थी. इसके साथ-साथ उन्होंने यह सरकार पर यह भी आरोप लगाया कि वंदे मातरम पर चर्चा इसलिए हो रही है क्योंकि पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं. वंदे मातरम का जब नाम लिया जाता है तो हमें पूरे इतिहास की याद आती है. उन्होंने आगे कहा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब वैसा पीएम नजर नहीं आते हैं जैसा पहले हुआ करते थे. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भाषण तो अच्छा देते हैं, लेकिन तथ्यों के मामले में कमजोर पड़ जाते हैं.मोदी जी जिस तरह तथ्यों को जनता के सामने रखते हैं, ये उनकी कला है. लेकिन मैं तो जनता की प्रतिनिधी हूं- कोई कलाकार नहीं हूं।

'वंदे मातरम पर बहस की जरूरत ही क्यों आई?'

प्रियंका ने कहा है कि जब हम वंदे मातरम का नाम लेते हैं तो हमें पूरे इतिहास की याद आती है जो स्वतंत्रता संग्राम का इतिहास था. उसकी पीढ़ा, नैतिकता और ब्रिटिश साम्राज्य का झुकना. वंदे मातरम ने भारत के लोगों को एक राजनीतिक और नैतिक आकांक्षा से जोड़ा. वंदे मातरम में सोए भारत को जगाने का काम किया है. आज की यह बहस कुछ अजीब सी लग रही है. यह गीत 150 सालों से नैतिकता का हिस्सा बन चुका है. आज इस बहस की क्या आवश्यकता है? हमारा यहां मकसद क्या है?

वंदे मातरम पर चर्चा के पीछे बंगाल का चुनाव- प्रियंका

प्रियंका गांधी ने आगे कहा कि वंदे भारत को लेकर आज जो बहस हो रही है उसके पीछे दो वजहें हैं. पहला बंगाल का चुनाव और दूसरी जिन्होंने देश के लिए कुर्बानियां दी उन पर ये सरकार नए-नए आरोप मढ़ना चाहती है. आपका मकसद है कि हम फिर से उसी अतीत में जाए क्योंकि ये सरकार भविष्य की ओर से देखना ही नहीं चाहती है. सच्चाई ये है कि आज प्रधानमंत्री मोदी दी वो पीएम नहीं रहे जो कभी हुआ करते थे. उनकी नीतियां देश को कमजोर कर रही है।

प्रियंका गांधी बोलीं- आज देश के लोग सरकार से खुश नहीं

कांग्रेस नेता ने कहा कि आज देश के लोग खुश नहीं हैं, परेशान हैं. तमाम समस्याओं से घिरे हुए हैं और उनका हल आप निकाल नहीं रहे हैं. इनके भी अपने लोग दबी जुबान से कहने लगे है कि सत्ता केंद्रित होने से देश को नुकसान हो रहा है. इसलिए आज हम वंदे मातरम पर चर्चा कर रहे हैं. वंदे मातरम देश के कण कण में जीवित है, इस पर बहस

नहीं होनी चाहिए. प्रियंका गांधी ने कहा कि यह सरकार वंदे मातरम के जरिए देश का ध्यान जनता के जरूरी मुद्दों से भटकाना चाहती है. वंदे मातरम पर स्वरूप पर सवाल उठाना उन महापुरुषों का अपमान है जिन्होंने इसे लेकर फैसले लिए. वंदे मातरम को विभाजित करने का आरोप लगाकर संविधान संभा में शामिल लोगों पर आरोप लगा रहे हैं. जहां तक जवाहर लाल नेहरू जी का बात है तो बता दें कि जितनी देर पीएम मोदी प्रधानमंत्री हैं वो उतने समय तक वो जेल में रहे. इसके बाद 17 साल तक प्रधानमंत्री रहे।

नेहरू ने इस देश के लिए क्या- क्या नहीं बनाया और किया- प्रियंका

उन्होंने कहा कि अगर नेहरू जी ने इसरो नहीं बनाया होता तो आज आप चांद पर नहीं पहुंचते. अगर उन्होंने गेल, भेल और सेल नहीं बनाया होता तो ये भारत कैसे बनता. पंडित जवाहर लाल नेहरू इस देश के लिए जिए. फिर भी मेरी एक सलाह ले लीजिए. अगर आपको नेहरू जी पर बहस करनी है तो आप आरोपों की एक पूरी लिस्ट तैयार कर लीजिए. इसके बाद जिस तरह से वंदे मातरम पर आज चर्चा हो रही है उसी तरह से कोई एक समय निर्धारित कर दीजिए. उसके बाद हम उस पर चर्चा करेंगे. आपको जितने भी सवाल तैयार करने कर लीजिए और संसद में चर्चा कर लेते हैं।

बड़े-बड़े शहरों में प्रदूषण है और हम वंदे मातरम पर चर्चा कर रहे- प्रियंका

प्रियंका गांधी ने कहा कि आज देश में इतनी महंगाई है, बेरोजगारी है लेकिन हम उस पर चर्चा क्यों नहीं करते हैं. महिलाओं के खिलाफ अपराधों पर हम चर्चा नहीं करते हैं. बड़े-बड़े शहरों में प्रदूषण है, लेकिन हम यहां बैठकर छोटी-छोटी बातों पर चर्चा कर रहे हैं. भविष्य पर चर्चा नहीं कर रहे हैं. हिम्मत है तो बात करिए कि देश में इतनी बेरोजगारी क्यों है? सच्चाई ये है कि इनका शासन गबन का शासन है. चुनाव से चुनाव तक राजनीति है. कांग्रेस के हर अधिवेशन में सामूहिक रूप से वंदे मातरम गाया जाता है. अपने देश की आत्म के इस महामंत्र को विवादित करके आप एक बहुत बड़ा पाप कर रहे हैं. ये राष्ट्रगीत वंदे मातरम हमेशा से हमें प्यारा है और रहेगा।

हमें तैयार रहना होगा, भारत-चीन बॉर्डर पर क्या चल रहा, वेस्टर्न कमांड के चीफ ने आखिर क्यों दी चेतावनी?

स्वतंत्र प्रभात संवाददाता

भारतीय सेना के पश्चिमी कमान के प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल मनोज कुमार कातियार ने रविवार को साफ शब्दों में कहा कि भारत को चीन और पाकिस्तान दोनों मोर्चों पर हर समय पूरी तरह तैयार रहना होगा. उत्तर प्रदेश के फतेहगढ़ में मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने चेतावनी दी कि देश की सीमाओं पर खतरे लगातार बने हुए हैं और इनसे निपटने के लिए किसी भी तरह की ढिलाई बर्दाश्त नहीं की जा सकती।

लेफ्टिनेंट जनरल कातियार ने कहा कि सेना की तैयारियों से किसी भी सूरत में समझौता नहीं किया जा सकता. उन्होंने कहा, 'सबसे पहली और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हमारी ऑपरेशनल तैयारियों से कोई समझौता नहीं होना चाहिए. चाहे वह चीन के साथ हमारी उत्तरी सीमाएं हों या फिर पश्चिमी सीमा, खतरा हर समय बना रहता है.' उन्होंने यह भी जोड़ा कि बदलते सुरक्षा परिदृश्य को देखते हुए सेना को हर वक्त अलर्ट रहना होगा और किसी भी चुनौती से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार रहना होगा।

भारतीय सेना की सबसे बड़ी ताकत क्या?

उन्होंने कहा कि सेना लगातार अपनी क्षमताओं को मजबूत कर रही है, लेकिन

इसके साथ-साथ उन मूल मूल्यों को भी बनाए रखना उतना ही जरूरी है, जो भारतीय सेना की पहचान हैं. लेफ्टिनेंट जनरल कातियार ने कहा, 'यह बेहद जरूरी है कि हमारी ऑपरेशनल तैयारियों में कोई कमी न रहे. इसके साथ ही मैं सशस्त्र बलों को एक और संदेश देना चाहता हूं कि हमें अपनी सेना के निष्पक्ष और धर्मनिरपेक्ष स्वरूप को हमेशा बनाए रखना है.' उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि भारतीय सेना राजनीति से ऊपर उठकर केवल राष्ट्रहित में काम करती रही है और आगे भी ऐसा ही होना चाहिए. हाल ही में पाकिस्तान के साथ बढ़े तनाव का जिक्र करते हुए पश्चिमी कमान प्रमुख ने कहा कि जब भी दुश्मन देश ने भारत के खिलाफ नापाक हरकत करने की कोशिश की है, भारतीय सेना ने उसका मुंहतोड़ जवाब दिया है. उन्होंने कहा, 'दोनों ही मोर्चों पर खतरे मौजूद हैं. हाल ही में जब पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ दुर्भावनापूर्ण आतंकी गतिविधि को अंजाम देने की कोशिश की, तो हमने ऑपरेशन सिंदूर के जरिए उन्हें करारा और मुहतोड़ जवाब दिया.' उनके इस बयान को हाल के सैन्य अभियानों और सीमा पर जवाबी कार्रवाई से जोड़कर देखा जा रहा है।

चीन सीमा को लेकर क्या बोले वेस्टर्न कमांड के चीफ?

लेफ्टिनेंट जनरल कातियार ने यह भी कहा कि भले ही पश्चिमी मोर्चे पर पाकिस्तान की ओर से लगातार चुनौतियां मिलती रहती हैं, लेकिन उत्तरी सीमा पर चीन से जुड़े खतरे को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता. उन्होंने कहा, 'पश्चिमी सीमा पर हमें हर समय सतर्क रहना पड़ता है, लेकिन इसके साथ ही हमें चीन की सीमा पर भी उतनी ही चौकसी बनाए रखनी होगी. दोनों ही मोर्चों पर चौबीसों घंटे तैयारी बनाए रखना अनिवार्य है.' उनके इस बयान को ऐसे समय में अहम माना जा रहा है, जब भारत की सीमाओं पर सुरक्षा चुनौतियां लगातार बदल रही हैं और क्षेत्रीय तथा वैश्विक हालात भी तेजी से करवट ले रहे हैं. सेना प्रमुख का यह साफ संदेश है कि देश की सुरक्षा सर्वोपरि है और इसके लिए हर स्तर पर सतर्कता, अनुशासन और पेशेवर प्रतिबद्धता जरूरी है।

सलमान रुश्दी ने मोदी सरकार में बढ़ते हिंदू राष्ट्रवाद और अभिव्यक्ति की आज़ादी पर हमलों पर चिंता जताई

स्वतंत्र प्रभात संवाददाता

नई दिल्ली- प्रसिद्ध लेखक सलमान रुश्दी ने हाल ही में भारत में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर हो रहे हमलों और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में बढ़ते हिंदू राष्ट्रवाद को लेकर चिंता जताई है. ब्लूमबर्ग को दिए एक इंटरव्यू में रुश्दी ने कहा कि वह मुसलमानों की छवि को लेकर और भारत के लेखकों, पत्रकारों और शिक्षाविदों पर बढ़ते दबाव को लेकर चिंतित हैं. रुश्दी ने इंटरव्यू में कहा, 'मैं इसे लेकर बहुत चिंतित हूं. भारत में मेरे बहुत से दोस्त हैं. हर कोई पत्रकारों, लेखकों, बुद्धिजीवियों, प्रोफेसरों आदि की स्वतंत्रता पर हो रहे हमलों से बेहद चिंतित है.' उन्होंने कहा कि देश की पहचान को नए सिरे से गढ़ने की कोशिश होती दिख रही है: ऐसा लगता है कि देश के इतिहास को दोबारा लिखने की इच्छा है, मूल रूप से यह कहने के लिए कि हिंदू अच्छे हैं और मुसलमान बुरे. वीएस नायपॉल ने इसे कभी 'घायल सभ्यता' कहा था, यह विचार कि भारत एक हिंदू सभ्यता है जिसे मुसलमानों के आने से चोट पहुंची. इस सोच को बहुत ज़्यादा बढ़ावा मिल रहा है. दशकों पहले

दिए गए अपने चेतावनी भरे बयानों पर बोलते हुए उन्होंने कहा, 'मुझे लगता है कि अगर आप एक लेखक हैं, अगर आप ध्यान देते हैं, तो कभी-कभी आपको आने वाली चीजें पहले ही दिख जाती हैं, और मुझे लगता है कि मैं वही कर रहा था, मैं ध्यान दे रहा था.' रुश्दी के इस बयान का संदर्भ यह है कि उन्होंने कई दशक पहले ही भारत में बढ़ती कट्टरता, नफरत और स्वतंत्रताओं पर बढ़ रहे हमलों को भांप लिया था।

2022 में रुशदी पर हुआ था हमला

1988 में द सैटेनिक वर्सेज़ के प्रकाशित होने के बाद से रुश्दी ईरान द्वारा जारी फतवे की छाया में जी रहे हैं. अगस्त 2022 में यह खतरा दोबारा हिंसक रूप में सामने आया, जब उन्हें पश्चिमी न्यूयॉर्क में एक व्याख्यान देने से ठीक पहले हमला कर घायल कर दिया गया. हमले से उबरने के बाद लेखक की एक आंख की रोशनी चली गई और वह अपने एक हाथ से अब कोई काम नहीं कर पाते हैं. हमलावर, 27 वर्षीय हादी मतार, बाद में हत्या के प्रयास और हमले का दोषी पाया गया और उसे 25 साल की जेल की सज़ा सुनाई गई।

भारत और द सैटेनिक वर्सेज़

उल्लेखनीय है कि भारत ने अक्टूबर 1988 में रुश्दी के उपन्यास द सैटेनिक वर्सेज़ के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया था. यह आदेश राजीव गांधी सरकार के दौरान वित्त मंत्रालय द्वारा जारी कस्टम नोटिस के तहत लागू किया गया था. सरकार ने इसके लिए यह तर्क दिया था कि मुस्लिम समुदाय, जो इस किताब को धार्मिक भावनाओं के विरुद्ध मानते थे, इसकी कड़ी प्रतिक्रिया दे सकते हैं. दिल्ली हाईकोर्ट ने 5 नवंबर 2024 को 37 साल पुराने इस आयात प्रतिबंध को प्रभावी रूप से हटा दिया. रुश्दी का जन्म 1947 में मुंबई में हुआ. उन्होंने इंग्लैंड के बोर्डिंग स्कूल के बाद कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से पढ़ाई की थी. साहित्य में योगदान के लिए उन्हें 2007 में 'नाइट' की उपाधि दी गई।

संक्षिप्त ख़बरें

समूह की महिलाओं का फूटा गुस्सा, अध्यक्ष व बीएमएम पर भ्रष्टाचार, धमकी और फर्जीवाड़े के लगाए गंभीर आरोप

हमीरपुर :- सरीला विकासखण्ड के जरिया गांव स्थित 'संकल्प प्रेरणा लघु उद्योग' के तहत चल रहे टीएचआर प्लांट में आज महिलाओं का गुस्सा फूट पड़ा। करीब 20 सदस्याओं वाले महिला समूह ने जोरदार हंगामा करते हुए अध्यक्ष सीमा और ब्लॉक मिशन मैनेजर संगीता व प्रशांत पर भ्रष्टाचार, उत्पीड़न और फर्जीवाड़े के गंभीर आरोप लगाए हैं। उत्तर प्रदेश के सरीला विकासखंड क्षेत्र के जरिया गांव स्थित टीएचआर प्लांट 'संकल्प प्रेरणा लघु उद्योग' द्वारा संचालित महिला समूह की सदस्याओं ने अध्यक्ष सीमा और ब्लॉक मिशन मैनेजर संगीता व प्रशांत पर गंभीर आरोप लगाए हैं। समूह में अध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष सहित लगभग 20 महिलाएं शामिल हैं। महिलाओं का आरोप है कि अध्यक्ष व बीएमएम संगीता समूह की सदस्याओं पर लगातार हटवाने की धमकी देते हैं और उनका उत्पीड़न करते हैं। कुछ समय पहले सेंटर पर चोरी हुई थी, जिसके बाद अध्यक्ष सीमा और बीएमएम संगीता ने सीसी टीवी फुटेज डिलीट कर दिया। सदस्याओं ने आरोप लगाया है कि अधिकारी उनसे घूस की मांग करते हैं और पैसा न देने पर हटाने की धमकी देते हैं। इतना ही नहीं, कई पदाधिकारियों द्वारा फर्जी उम्र दर्ज कर 40 वर्ष बताकर हटाने की कोशिश की जा रही है। महिलाओं ने यह भी कहा कि मशीनें खराब होने पर कई दिन तक कोई सुनवाई नहीं होती और छुट्टी होने पर भी सूचना नहीं दी जाती। आक्रोशित महिलाओं ने निष्पक्ष जांच, कार्रवाई और अध्यक्ष व बीएमएम को हटाने की मांग उठाई है।

जम्मू-कश्मीरः हिरासत में लिया गया चीनी नागरिक, वीजा नियमों के उल्लंघन का आरोप, फोन से मिली अहम जानकारी

स्वतंत्र प्रभात संवाददाता

कश्मीर में अलर्ट सुरक्षा एजेंसियों ने चीन के नागरिक को हिरासत में लिया है. जो बिना इजाजत लद्दाख और कश्मीर के संवेदनशील इलाकों में घूम रहा था. 29 साल का हू कोंगताई 19 नवंबर को टूरिस्ट वीजा पर दिल्ली आया था जिससे उसे वाराणसी, आगरा, नई दिल्ली, जयपुर, सारनाथ, गया और कुशीनगर में बौद्ध धार्मिक स्थलों पर जाने की इजाजत थी. जानकारी के मुताबिक हू कोंगताई 20 नवंबर को दिल्ली से लेह की फ्लाइट पकड़कर सीधे लद्दाख पहुंच गया. उसने लेह एयरपोर्ट पर स्थित फॉरेनर्स रीजनल रजिस्ट्रेशन ऑफिस काउंटर पर रजिस्ट्रेशन नहीं कराया. नियम के मुताबिक किसी भी विदेशी को लेह एयरपोर्ट पर मौजूद FRRO काउंटर पर रजिस्ट्रेशन कराना होता है, लेकिन कोंगताई ने ऐसा नहीं किया।

CRPF की तैनाती के बारे में ले रहा था जानकारी

अधिकारियों ने बताया कि अपने प्रवास के दौरान कोंगताई ने तीन दिनों तक जंस्कार इलाके का दौरा किया और 1 दिसंबर को श्रीनगर पहुंचने से पहले हिमालयी शहर में महत्वपूर्ण जगहों पर गया. अधिकारियों ने बताया कि उसके फोन की हिस्ट्री की जांच से पता चला कि वह घाटी में सीआरपीएफ की तैनाती के बारे में जानकारी ढूंढ रहा था और उससे कई एजेंसियां पूछताछ कर रही हैं।

भारतीय सिम कार्ड का इंतजाम किया

अधिकारियों के अनुसार हू कोंगताई ने बाजार से एक भारतीय सिम कार्ड का इंतजाम किया था. श्रीनगर में रहते हुए वो एक गैर पंजीकृत गेस्ट हाउस में रुका था. चीनी नागरिक हरवान में एक बौद्ध धार्मिक स्थल पर भी गया. जहां पिछले साल एक मुठभेड़ में लश्कर-ए-तैयबा का एक आतंकवादी मारा गया था।

अवंतीपोरा के खंडहरों का भी दौरा

अधिकारियों और उसके फोन से निकाले गए डेटा के अनुसार उसने दक्षिण कश्मीर में अवंतीपोरा के खंडहरों का भी दौरा किया था जो दक्षिण कश्मीर में सेना के विक्टर फोर्स मुख्यालय के पास स्थित है. अपने प्रवास के दौरान वह शंकराचार्य पहाड़ियां, हजरतबल और डल झील के किनारे मुगल गार्डन भी गया. अधिकारियों ने बताया कि उसके फोन की हिस्ट्री में सीआरपीएफ की तैनाती और संविधान के अनुच्छेद 370 से संबंधित सर्च दिखे हैं. जिसे अगस्त 2019 में जम्मू-कश्मीर का विशेष दर्जा समाप्त करने के लिए निरस्त कर दिया गया था।

पूछताछ में कही ये बात

जानकारी के मुताबिक कोंगताईने बोस्टन विश्वविद्यालय से भौतिकी में स्नातक किया है. पूछताछ में उसने बताया कि उसे यात्रा करना पसंद है. उसके पासपोर्ट से पता चलता है कि उसने अमेरिका, न्यूज़ीलैंड, ब्राज़ील, फ़िजी और हांगकांग सहित कई देशों की यात्रा की है. अधिकारियों का कहना है कि उसने वीजा नियमों का गंभीर उल्लंघन किया है और ऐसी स्थिति में अधिकतम कार्रवाई उसे वापस भेजना ही है. फिलहाल सुरक्षा एजेंसियां उससे पूछताछ कर रही हैं और उसके फोन डेटा की जांच की जा रही है।

उत्तर प्रदेश में बेदखली का सामना कर रहे असम के प्रवासी मज़दूरों में दहशत

स्वतंत्र प्रभात संवाददाता

नई दिल्ली- 22 नवंबर को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभी ज़िलाधिकारियों को कथित अवैध प्रवासियों की पहचान करने और उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के निर्देश जारी किए थे. साथ ही प्रत्येक ज़िले में पहचाने गए घुसपैठियों को रखने के लिए अस्थायी डिटेंशन सेंटर स्थापित करने के भी निर्देश दिए गए थे. 38 वर्षीय इम्तियाज़ अली के लिए, जो फूलबाग बहादुरपुर की एक झुग्गी बस्ती में रहते हैं, 4 दिसंबर का दिन अन्य दिनों की तरह ही शुरू हुआ. लेकिन उस दिन तब सब कुछ बदल गया जब लखनऊ नगर निगम की एक टीम मेयर सुषमा खरख्वाल के नेतृत्व में वहां पहुंची और बांग्लादेशी और रोहिंग्या बताकर अवैध रूप से रह रहे लोगों की पहचान के लिए दस्तावेज़ों की जांच करने लगी. खरख्वाल ने दावा किया कि गुदंबा थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले इस इलाके के कई निवासी वैध दस्तावेज़ पेश करने में विफल रहे और उन्होंने उन्हें बाहर निकालने की बात कही. नगर निगम अधिकारियों द्वारा की जा रही इस जांच के कथित वीडियो क्लिप सोशल मीडिया पर वायरल हो गए. अखबार के अनुसार, असम के बारपेटा निवासी अली ने कहा, 'मैं वो दिन कभी नहीं भूलूंगा. मेरे परिजन रो रहे थे क्योंकि अधिकारी हमारी बात सुनने को तैयार नहीं थे. उन्होंने मेरी ठेला-गाड़ी छीन ली और हमें 15 दिनों में झुग्गी खाली करने को कहा. उन्हें पहले हमारे दस्तावेज़ देखने चाहिए थे, लेकिन वे सीधे हमारे घरों में घुस आए और हमारी रोज़ी-रोटी छीन ली।'

अली ने बताया कि इस घटना से असम से आकर लखनऊ में कबाड़ बीनने और निजी व्यापारियों को बेचकर रोज़ी कमाने वाले 50 से अधिक परिवारों में दहशत फैल गई है. उन्होंने कहा, 'हम गरीब लोग हैं और केवल पैसे कमाने के लिए लखनऊ आए हैं. हम महीने में 8 से 10,000 रुपये कमाते हैं और निजी ज़मीन के मालिक को 1,000 रुपये प्रति परिवार किराया देते हैं. हम भारतीय नागरिक हैं और हमने कभी कोई गैरकानूनी काम नहीं किया.' असम से आए झुग्गी के एक अन्य व्यक्ति सुजान अली ने कहा, 'हम पिछले 18 साल से लखनऊ में रह रहे हैं और हमारे पास आधार, पैन और वोटर आईडी जैसे सभी वैध दस्तावेज़ हैं. हमारे नाम राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (एनआरसी) में भी दर्ज हैं. अगर कोई अवैध रूप से यहां रह रहा है तो हम उसे पुलिस के हवाले कर देंगे, लेकिन हमें आतंकित मत कीजिए. हमारी ठेला-गाड़ियां वापस कीजिए और हमें काम करने दीजिए. मैं 4 दिसंबर से काम नहीं कर पाया हूं।'

विपक्ष ने कार्रवाई पर उठाए सवाल

विपक्षी दलों ने इस अभियान को 'राज्य में भाजपा सरकार द्वारा डराने-धमकाने की

रणनीति' बताया और लोगों के पहचान पत्रों की जांच करने के मेयर के अधिकार पर सवाल उठाया. रविवार को कांग्रेस के एक प्रतिनिधिमंडल ने इस झुग्गी बस्ती का दौरा किया और असम से आए प्रवासियों के साथ खड़े रहने का वादा किया. उसने नगर निगम अधिकारियों से कथित 'उत्पीड़न' के लिए माफ़ी मांगने की भी मांग की. कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव शहनवाज़ आलम ने कहा, 'हमने झुग्गी बस्ती का दौरा किया और पाया कि उनके पास सभी वैध पहचान पत्र हैं, जो यह साबित करता है कि वे भारतीय नागरिक हैं. वे असम के उन इलाकों से आए हैं जहां अक्सर बाढ़ आती है, इसलिए रोज़ी-रोटी की तलाश में यहां आए हैं. झुग्गी निजी ज़मीन पर स्थित है, तो फिर नगर निगम उन्हें 15 दिनों में खाली करने को क्यों कह रहा है? उनकी ठेला-गाड़ियां क्यों छीनी गईं? यह गलत है. हम अधिकारियों से माफ़ी की मांग करते हैं. भाषा या क्षेत्र के आधार पर उठाए गए ऐसे कदम देश को विभाजित करेंगे.' 'घुसपैठियों' के खिलाफ कार्रवाई के बीच सीएम ने कहाः किसी को रखने से पहले उसकी पहचान सत्यापित करें समाचार एजेंसी पीटीआई के मुताबिक, इस बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोमवार को नागरिकों से सतर्क रहने और किसी को काम पर रखने से पहले उसकी पहचान का सत्यापन कराने की अपील की. उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश ने सुरक्षा और सामाजिक संतुलन बनाए रखने के लिए अवैध प्रवासियों के खिलाफ सख्त और निर्णायक कार्रवाई शुरू की है. उनकी यह अपील राज्यभर में 'घुसपैठियों' के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के बीच आई है, जो पिछले सप्ताह अधिकारियों को दिए गए निर्देशों के बाद शुरू किया गया था. एक्स पर एक पोस्ट में आदित्यनाथ ने कहा, 'माननीय सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान एक अत्यंत महत्वपूर्ण टिप्पणी की है कि घुसपैठियों के लिए रेड कार्पेट नहीं बिछाया जा सकता. इससे यह स्पष्ट होता है कि घुसपैठिए किसी भी कीमत पर स्वीकार्य नहीं हैं.' उन्होंने कहा कि संसाधन देश के नागरिकों के लिए हैं, न कि अवैध प्रवासियों के लिए, और राज्य में सुरक्षा, सामाजिक संतुलन और मजबूत कानून-व्यवस्था बनाए रखना उनकी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है।

ज्ञात हो कि 2 दिसंबर को सुप्रीम कोर्ट ने भारत में रह रहे रोहिंग्याओं की कानूनी स्थिति पर कड़ी टिप्पणी की थी और सवाल उठाया था कि जब देश के अपने नागरिक गरीबी से जूझ रहे हैं तो 'घुसपैठियों' का 'रेड कार्पेट वेलकम' क्यों किया जाए. मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्या बागची की पीठ ने यह टिप्पणी एक अधिकार कार्यकर्ता द्वारा दायर बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका की सुनवाई के दौरान की, जिसमें दिल्ली में हिरासत से कुछ रोहिंग्याओं के लापता होने का आरोप लगाया गया था. यूपी के मुख्यमंत्री ने लोगों से सतर्क रहने और किसी को रोजगार देने से पहले उसकी पहचान का उचित सत्यापन सुनिश्चित करने का आग्रह किया. उन्होंने कहा, 'राज्य की सुरक्षा हमारी सामूहिक जिम्मेदारी है, क्योंकि सुरक्षा ही समृद्धि की नींव है.' मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में अवैध रूप से रह रहे रोहिंग्या और बांग्लादेशी नागरिकों के खिलाफ सख्त अभियान शुरू किया गया है. उन्होंने बताया कि सभी शहरी स्थानीय निकायों को संदिग्ध विदेशी नागरिकों की पहचान करने और उनकी सूची तैयार करने के निर्देश दिए गए हैं. उन्होंने कहा कि कल्याणकारी योजनाओं का लाभ वंचितों तक पहुंचने के लिए है और उसे भटकाया नहीं जा सकता. उन्होंने कहा, 'इसी उद्देश्य से एक विशेष दस्तावेज़ सत्यापन अभियान चलाया जा रहा है और घुसपैठियों की पहचान कर उन्हें आगे की कार्रवाई के लिए निरोध केंद्रों में भेजा जा रहा है.' उन्होंने बताया कि इस प्रक्रिया को सुगम बनाने के लिए प्रत्येक मंडल में डिटेंशन केंद्र स्थापित किए जा रहे हैं।

मौलाना सलीम मेमोरियल क्रिकेट टूर्नामेंट के फाइनल में केजीएन मौदहा ने दिल्ली को हराकर फाइनल जीता

हमीरपुर :- मौदहा के रहमानियां कॉलेज में चल रहे मौलाना सलीम मेमोरियल क्रिकेट टूर्नामेंट का फाइनल मैच रविवार के दिन के जीएन मौदहा और दिल्ली के बीच खेला गया।20-20 ओवरों के मैच में दिल्ली ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 20 ओवरों में 6 विकेट खोकर184 रन बनाए। दिल्ली की ओर से ओपनिंग बल्लेबाजी करने आए अभय यादव व अमन ने टीम को अच्छी शुरुआत दिलाई लेकिन मीशम अब्बास की गेंद पर अभय यादव 25 रनों पर आउट हो गए।वहीं दिल्ली के सौरभ सिंह ने 37 और समन्वय ने 59 रनों की शानदार अर्धशतकीय पारी खेली।केजीएन मौदहा ने 185 रनों के लक्ष्य को पाने के लिए अपने ओपनर बल्लेबाज अभय व हर्षित को उतारा जिन्होंने टीम को शानदार शुरुआत दिलाई और अभय ने 29 तो हर्षित ने 50 रनों की शानदार पारी खेली। प्रियांशु ने 72 रन बनाकर नाबाद रहे और टीम को 6 विकेट से फाइनल में जीत दिलाई।मैन ऑफ द मैच प्रियांशु को दिया जिस और मैन आफ द सीरीज अभय चुने गए।मुख्य अतिथि ने ट्रफी सहित विजेता टीम को 80 हजार एवं उपविजेता को 60 हजार रुपए का नकद पुरस्कार देकर सम्मानित किया।फाइनल मैच में अंपायर डॉ आसिफ परवेज व अज़ीज़ मिंटू रहे , स्कोरिंग समीर व कमेंट्री अब्दुल कादिर ने की। इस दौरान कमेटी अध्यक्ष बीतू बादशाह, मोहम्मद अहमद (गुड्डू भाई), ममनून बंगस, अनीस, कलीम उल्लाह सहित समस्त कमेटी सदस्य उपस्थित रहे।

पश्चिम बंगाल में कानून व्यवस्था पर गहराता संकट और 2026 की चुनावी सरगर्मी

पश्चिमी बंगाल में कानून व्यवस्था की स्थिति को लेकर राजनीतिक और सामाजिक दोनों ही स्तरों पर लगातार बहस तेज हो रही है। हाल के दिनों में मुर्शिदाबाद में बम मिलने की घटनाओं, सीमावर्ती इलाकों में बढ़ती अवैध घुसपैठ, रोहिंग्या नेटवर्क की सक्रियता और प्रशासन की कथित उदासीनता ने आम जनजीवन में असुरक्षा की भावना भर दी है। राज्य में होने वाले 2026 के विधानसभा चुनावों से पहले यह मुद्दा और भी अधिक राजनीतिक रंग ले चुका है। भारतीय जनता पार्टी इसे सबसे बड़ा चुनावी सवाल बनाकर जनता के बीच जा रही है जबकि राज्य सरकार विपक्ष के आरोपों को राजनीतिक साजिश बताकर खारिज करने में लगी है। लेकिन सच्चाई यह है कि जमीन पर कानून व्यवस्था को लेकर असंतोष बढ़ रहा है और आम नागरिक सुरक्षा को लेकर चिंतित हैं।पश्चिम बंगाल की राजनीति में धर्म आधारित तनाव, सीमावर्ती जिलों में अवैध घुसपैठ, राजनीतिक हिंसा और प्रशासनिक पक्षपात के आरोप लंबे समय से मौजूद रहे हैं। मगर पिछले कुछ वर्षों में यह स्थिति और अधिक जटिल होती दिखाई दे रही है। राज्य के कई जिलों से समय समय पर बम बरामद होने की खबरें आती रही हैं। मुर्शिदाबाद, मालदा, उत्तर दिनाजपुर और नदिया जैसे जिले न केवल संवेदनशील क्षेत्र बन चुके हैं बल्कि इन जिलों में कई गिरोह सक्रिय हैं जिन पर बांग्लादेशी नेटवर्क से जुड़े होने के आरोप भी लगते रहे हैं। यह इलाका बार बार कट्टरपंथी और आपराधिक गतिविधियों का केंद्र बनता रहा है और यही कारण है कि यहां पर मिलने वाले बम और हथियार सामान्य घटना की तरह दिखाई देने लगे हैं। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि पश्चिम बंगाल की मौजूदा परिस्थितियाँ किसी भी लोकतांत्रिक राज्य के लिए गंभीर खतरे की निशानी हैं। कानून व्यवस्था का विघटन न तो एक रात में होता है और न ही यह एक प्रशासन की अकेली नाकामी का संकेत होता है। इसके पीछे वर्षों से चले आ रहे राजनीतिक समझौतों, वोट बैंक की राजनीति और अवैध गतिविधियों पर ढील जैसी कई परतें शामिल होती हैं। राज्य की वर्तमान सरकार पर भी इसी तरह के आरोप लगते रहे हैं कि उसने मुस्लिम वोट बैंक को साधने के लिए रोहिंग्या और बांग्लादेशी घुसपैठ के खिलाफ कठोर कदम नहीं उठाए। कई विपक्षी नेता यह दावा करते हैं कि सीएम ममता बनर्जी घुसपैठ के मुद्दे को गंभीरता से नहीं लेतीं और इसे राजनीतिक लाभ के हिसाब से देखने की कोशिश होती है। इस कारण सीमावर्ती क्षेत्र एक तरह से पनाहगाह बनते जा रहे हैं जहां वैध और अवैध की रेखा धीरे धीरे धुंधली होती जा रही है।

रोहिंग्या घुसपैठ और उससे जुड़े आपराधिक नेटवर्क ने बंगाल की कानून व्यवस्था को न केवल चुनौती दी है बल्कि यह सामाजिक तनाव का कारण भी बन रहा है। स्थानीय लोगों का कहना है कि सीमावर्ती इलाकों में रोहिंग्या बस्तियां लगातार बढ़ी हैं और इन बस्तियों में कई संदिग्ध गतिविधियाँ पनपती हैं। इससे स्थानीय युवाओं में बेरोजगारी, अपराध और नशे की समस्या भी बढ़ी है। पुलिस पर यह आरोप भी है कि वह कई मामलों में कार्रवाई नहीं करती या फिर राजनीतिक दबाव में कार्रवाई रोक दी जाती है। जब जनता को न्याय नहीं मिलता तो उसे लगता है कि पूरा तंत्र ढह चुका है और उसकी सुरक्षा भगवान भरोसे है।

हिंदू समुदाय पर अत्याचार की घटनाओं और मंदिरों या धार्मिक कार्यक्रमों पर हमलों को लेकर भी माहौल तनावपूर्ण होता रहा है। कई रिपोर्टें सामने आई जिनमें कहा गया कि यदि किसी धार्मिक अल्पसंख्यक से संबंधित मामला होता है तो प्रशासन तेजी दिखाता है लेकिन हिंदू समुदाय से जुड़े मुद्दों पर उदासीनता रखी जाती है। इस कथित दोहरे मानदंड ने सरकार की छवि कमजोर की है। कई बार ऐसे मामले सामने आए जब दुष्कर्म, हिंसा और हमलों की घटनाओं को प्रशासन ने दबाने की कोशिश की और पुलिस ने एफआईआर दर्ज करने में देरी की। यह स्थिति लोगों के मन में यह धारणा और मजबूत करती है कि कानून का शासन खत्म हो चुका है और पुलिस राजनीतिक आदेशों पर चलने को मजबूर है।

2026 के विधानसभा चुनाव की तैयारियों में भाजपा ने इन सभी मुद्दों को केंद्र में रखकर रणनीति बनानी शुरू कर दी है। पार्टी इसे कानून व्यवस्था की लड़ाई और बंगाल के भविष्य की लड़ाई के रूप में पेश कर रही है। भाजपा नेताओं का कहना है कि राज्य में हिंदुओं पर अत्याचार बढ़ा है और उनके धार्मिक अधिकारों का खुलेआम उल्लंघन किया जा रहा है। इन घटनाओं के खिलाफ आवाज उठाने वाले लोग भी दमन के शिकार बनते जा रहे हैं। भाजपा यह सवाल उठा रही है कि क्या राज्य सरकार सभी नागरिकों के साथ समान व्यवहार कर रही है या फिर वोट बैंक को मजबूत करने के लिए विशेष समूहों को संरक्षण दे रही है।

भाजपा का यह भी कहना है कि अगर बंगाल में बदलाव चाहिए तो सुरक्षा और कानून व्यवस्था की बहाली सबसे पहली प्राथमिकता होनी चाहिए। इसके लिए पुलिस प्रशासन को राजनीतिक दबाव से मुक्त करना आवश्यक होगा। पार्टी यह दावा करती है कि उसकी सरकार आने पर कानून व्यवस्था पर शून्य सहनशीलता की नीति अपनाई जाएगी। सीमावर्ती जिलों में सख्त निगरानी, राष्ट्रीय सुरक्षा के मानकों के अनुसार आतंक और घुसपैठ के खिलाफ अभियान और प्रशासनिक सुधार किए जाएंगे। भाजपा आम नागरिकों के सामने यह सवाल भी रख रही है कि क्या वे ऐसा राज्य चाहते हैं जहां अपराधी बेखौफ हों और आम जनता डर में जीने को मजबूर। पार्टी का कहना है कि सुरक्षित वातावरण ही विकास की असली नींव है और जब तक कानून व्यवस्था दुरुस्त नहीं होगी तब तक राज्य आर्थिक और सामाजिक दोनों क्षेत्रों में पिछड़ता रहेगा।

पश्चिम बंगाल की राजनीति में हिंसा कोई नई बात नहीं है लेकिन पिछले कुछ वर्षों में राजनीतिक हिंसा की मात्रा और क्रूरता बढ़ी है। चुनावों के दौरान कई कार्यकर्ताओं की हत्या, हमले, घर जलाना और मारपीट की घटनाएँ लगातार सामने आती रही हैं। इससे लोकतांत्रिक प्रक्रिया पर नकारात्मक असर पड़ता है और चुनावों का माहौल भय और आतंक में बदल जाता है। कानून व्यवस्था का अर्थ सिर्फ अपराधियों को पकड़ना नहीं होता बल्कि वह नागरिक स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की आजादी और राजनीतिक अधिकारों की रक्षा भी होती है। यदि किसी राज्य में लोग स्वतंत्र रूप से वोट नहीं डाल सकते या किसी पार्टी का झंडा नहीं लगा सकते तो वह राज्य लोकतांत्रिक मूल्यों की परीक्षा में असफल माना जाएगा।

राज्य में भ्रष्टाचार का मुद्दा भी मौजूदा सरकार के लिए बड़ा सिरदर्द बना हुआ है। शिक्षक भर्ती घोटाले से लेकर नगरपालिका और पंचायतों में भ्रष्टाचार के आरोप लगातार चर्चा में रहे। कई वरिष्ठ नेताओं और अधिकारियों की गिरफ्तारी हुई लेकिन विपक्ष का आरोप है कि सरकार ने इन मामलों को दबाने का प्रयास किया और वास्तविक लाभार्थियों को बचाया। भ्रष्टाचार और कानून व्यवस्था का पतन साथ साथ चलता है। जहां भ्रष्टाचार होता है वहां अपराधियों को संरक्षण मिलता है और जहां अपराधी मजबूत होते हैं वहां जनता कमजोर होती है।

पश्चिम बंगाल के भविष्य का सवाल अब केवल राजनीतिक नहीं बल्कि सामाजिक और राष्ट्रीय सुरक्षा से भी जुड़ गया है। राज्य की भौगोलिक स्थिति, अंतरराष्ट्रीय सीमा और संवेदनशील जिलों को देखते हुए यहां सुरक्षा की चुनौतियाँ स्वभाविक रूप से अधिक हैं। इसलिए यह आवश्यक है कि सरकारें किसी भी समुदाय या वोट बैंक से ऊपर उठकर कड़ी और निष्पक्ष नीति बनाएं। लेकिन अगर राजनीतिक लाभ के लिए सुरक्षा के मुद्दे की अनदेखी होती रही तो इसका असर पूरे देश पर पड़ेगा।आगामी चुनाव पश्चिम बंगाल के लिए निर्णायक साबित हो सकते हैं। जनता यह तय करेगी कि वह किस प्रकार का नेतृत्व चाहती है। वह ऐसा शासन चाहती है जहां अपराधियों का दबदबा हो या ऐसा शासन जहां कानून का राज कायम रहे। वह ऐसा प्रशासन चाहती है जहां एफआईआर दर्ज कराने के लिए गुहार लगानी पड़े या ऐसा प्रशासन जहां न्याय को प्राथमिकता मिले। वह ऐसा राज्य चाहती है जहां घुसपैठ का जाल फैलता जाए या ऐसा राज्य जहां सीमाएँ सुरक्षित और समाज स्थिर हो।

पश्चिम बंगाल के लोग हमेशा से सांस्कृतिक रूप से समृद्ध और लोकतांत्रिक विचारों वाले रहे हैं। लेकिन आज वे जिस असुरक्षा और अव्यवस्था का सामना कर रहे हैं वह चिंता का विषय है। जरूरत इस बात की है कि राजनीतिक दल जनता की भावनाओं और प्रदेश की वास्तविक समस्याओं को समझें। मुद्दे चाहे घुसपैठ हों या राजनीतिक हिंसा, चाहे भ्रष्टाचार हो या धार्मिक असंतुलन, इनका समाधान केवल मजबूत इच्छाशक्ति और पारदर्शी शासन से ही संभव है। यदि सरकारें अपने दायित्वों का ईमानदारी से पालन करें तो पश्चिम बंगाल न केवल सुरक्षित बन सकता है बल्कि विकास की नई ऊंचाइयों को भी छू सकता है।2026 का चुनाव केवल सत्ता परिवर्तन का अवसर नहीं बल्कि एक ऐसा मोड़ है जो यह तय करेगा कि राज्य किस दिशा में जाएगा। जनता की सुरक्षा, सामाजिक सौहार्द और कानून व्यवस्था जैसे मूल प्रश्न इस चुनाव की वास्तविक धुरी बन चुके हैं। यही मुद्दे आने वाले वर्षों में बंगाल के राजनीतिक और सामाजिक भविष्य की दिशा तय करेंगे।

कांतिलाल मांडोत

संपादकीय

बंगाल की मुस्लिम राजनीति पर हुमायूं कबीर का प्रहार

पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में 6 दिसंबर को तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) के निलंबित विधायक हुमायूं कबीर ने अयोध्या की बाबरी मस्जिद की तर्ज पर एक नई मस्जिद की आधारशिला रखी। यह सिर्फ एक धार्मिक ढांचे का निर्माण नहीं, बल्कि कई स्तरों पर पहचान, भावनाओं और सत्ता-राजनीति के प्रतीकों को एक साथ सक्रिय करने वाला क्षण है। जिस तारीख को बाबरी विध्वंस हुआ था, उस दिन यह कार्यक्रम आयोजित करना और बाहरी धर्मगुरुओं तथा हजारों की भीड़ को जुटाना इसे महज स्थानीय आयोजन के दायरे से बाहर ले जाता है। यह एक खुला राजनीतिक संकेत है कि बंगाल का अल्पसंख्यक परिदृश्य अब एक नए दौर में प्रवेश कर चुका है जहाँ धार्मिक पहचान और राजनीतिक महत्वाकांक्षा एक-दूसरे का पूरक बनकर उभर रही हैं।

टीएमसी ने मस्जिद-निर्माण को लेकर फैले तेज राजनीतिक संकेतों को भाँपते हुए कबीर को 4 दिसंबर को ही निलंबित कर दिया, ताकि उसके ऊपर लगने वाले 'तुष्टिकरण' के आरोपों को कम किया जा सके। पार्टी का तर्क है कि मस्जिद बनाना किसी व्यक्ति या समूह का अधिकार है, लेकिन बाबरी से जुड़ा नामकरण और तारीख का चयन ऐसी अनावश्यक उत्तेजना है जो बंगाल की दशकों पुरानी धर्मनिरपेक्ष राजनीतिक धारा को मुश्किल में डाल देता है। टीएमसी को यह भी भली-भाँति पता है कि भाजपा इस प्रतीकात्मक राजनीति का उपयोग एक व्यापक नैरेटिव बनाने में करेगी कि राज्य सरकार का रवैया वर्षों से इस तरह के कदमों को प्रोत्साहन देता रहा है। निलंबन इसलिए पार्टी की एक रणनीतिक प्रतिक्रिया थी, ताकि वह आधिकारिक रूप से खुद को इस पूरे आयोजन से अलग दिखा सके और यह संदेश दे कि यह उसका एजेंडा नहीं है। लेकिन राजनीतिक वास्तविकता इससे कहीं अधिक जटिल है, क्योंकि यही कार्रवाई मुस्लिम समाज के भीतर एक संदेह भी पैदा कर सकती है कि पार्टी अब उन मुद्दों से दूरी बनाने लगी है जिन्हें एक बड़ा वर्ग 'सम्मान' और 'हक़' के सवाल से जोड़कर देखता है।

हुमायूं कबीर जिस तरह इस मस्जिद को मुसलमानों की 'इज़्ज़त की लड़ाई' बता रहे हैं, वह इस पूरे घटनाक्रम को धार्मिक पहचान से सीधे जोड़ देता है। उनका यह दावा कि 25 बीघा जमीन पर मस्जिद के साथ अस्पताल, मेडिकल कॉलेज, होटल और हेलिपैड भी बनेगा, इसे एक विशाल सामुदायिक-राजनीतिक परियोजना का रूप देता है। 22 दिसंबर को नया दल बनाने और लगभग 130-135 सीटों पर उम्मीदवार उतारने की उनकी घोषणा यह साफ़ करती है कि यह केवल धार्मिक आस्था या भावनाओं का मुद्दा नहीं, बल्कि एक नया, अलग मुस्लिम वोट-बैंक खड़ा करने की महत्वाकांक्षा है। यह बंगाल के राजनीतिक मानचित्र में मुस्लिम राजनीति के भीतर एक नए प्रतिस्पर्धी मॉडल का उदय है, जो पहली बार इतनी स्पष्टता से सामने आया है।

मसलन, बंगाल में लंबे समय से मुस्लिम वोट काफी हद तक एकजुट होकर टीएमसी को मिलता रहा है, जिससे पार्टी को एक मज़बूत चुनावी आधार हासिल था। लेकिन कबीर का यह कदम इस एकजुटता को चुनौती दे सकता है। मुस्लिम वोट का आंशिक कटाव भी उन जिलों में निर्णायक प्रभाव डाल सकता है, जहाँ सीटें बेहद कम अंतर से तय होती हैं

मुर्शिदाबाद, मालदा, उत्तर व दक्षिण 24 परगना जैसे जिले इसके केंद्र बन सकते हैं। इस प्रकार यह घटना मुस्लिम समाज के भीतर एक आंतरिक ध्रुवीकरण को जन्म देती है: एक ओर वे जो पहचान के सवाल को प्राथमिक मानते हैं और दूसरी ओर वे जो मानते हैं कि राष्ट्रीय स्तर पर इसका नकारात्मक असर मुसलमानों को और अधिक असुरक्षित बनाता है। कांग्रेस और कई स्थानीय मुस्लिम नेताओं ने इसी आशंका का इज़हार किया है कि मस्जिद को 'बाबरी' के प्रतीक से जोड़ना एक बड़ा राजनीतिक-धार्मिक उबाल पैदा करेगा, जिसके परिणाम व्यापक होंगे और जिनका बोझ छोटे इलाकों के आम मुसलमानों को राष्ट्रीय स्तर पर उठाना पड़ेगा।

भाजपा इस समय को एक अवसर के रूप में देख रही है। उसके लिए यह एक राजनीतिक स्वर्ण-क्षण है जहाँ वह मुस्लिम पहचान-आधारित लामबंदी को टीएमसी के दीर्घकालीन 'तुष्टिकरण' के परिणाम के रूप में पेश कर सकती है। भाजपा का संदेश बहुत सीधा और चुनावी दृष्टि से प्रभावी है कि यह स्थिति अचानक पैदा नहीं हुई, बल्कि राज्य सरकार के वर्षों तक की गई नीतियों और रुख ने ऐसे अवसरों को जन्म दिया है। भले ही टीएमसी ने अब कबीर को बाहर का रास्ता दिखा दिया हो, लेकिन भाजपा जिस तरह इस पूरे प्रकरण को टीएमसी की राजनीतिक विरासत से जोड़ रही है, वह चुनावी मानस को लगातार प्रभावित करेगा।

इस परिदृश्य का सबसे संवेदनशील पहलू कानून-व्यवस्था है। हाई कोर्ट ने कार्यक्रम को रोकने से इंकार करते हुए राज्य सरकार को पूरी जिम्मेदारी सौंपी। इसका सीधा अर्थ है कि आने वाले महीनों में इस स्थल से जुड़ा कोई भी तनाव चाहे प्रशासनिक चूक हो या सामाजिक तनाव सीधे सरकार की जवाबदेही का प्रश्न बनेगा। चुनावी समय में यह सबसे जोखिम भरा क्षेत्र है, क्योंकि किसी भी छोटे विवाद को राजनीतिक विमर्श में बड़े संकट के रूप में पेश किया जा सकता है।

इन समग्र परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए यह स्पष्ट है कि यह घटना महज़ एक धार्मिक ढांचे की नींव रखने की नहीं है। यह बंगाल के 2026 के विधानसभा चुनाव के लिए एक 'ट्रिगर इवेंट' बन चुकी है, जिसने एक साथ तीन प्रमुख प्रवृत्तियों को उजागर कर दिया है: मुस्लिम राजनीति का संभावित विखंडन, ममता बनर्जी के लिए दोतरफ़ा दबाव जहाँ उन्हें भाजपा के आरोपों को निष्प्रभावी रखना है और साथ ही मुस्लिम वोट को भी अपने से दूर नहीं जाने देना है और भाजपा के लिए ध्रुवीकरण आधारित एक नए शक्तिशाली राजनीतिक नैरेटिव का उभार। इन तीनों का सम्मिलित प्रभाव यह सुनिश्चित करता है कि आने वाले महीनों में बंगाल की राजनीति सिर्फ विकास, योजनाओं या प्रशासनिक बहसों तक सीमित नहीं रहेगी। पहचान और भावनात्मक इतिहास से जुड़े सवाल इस चुनाव का केंद्र बनने जा रहे हैं। यह घटना, भले ही प्रतीकात्मक दिखती हो, लेकिन इसके राजनीतिक परिणाम बेहद ठोस और दूरगामी होंगे।

महेन्द्र तिवारी

इंडिगो के संकट से सरकार की नीतियों पर भी सवाल

सरकार को नियम बनाने और उनको लागू करने के लिए व्यवहारिक अड़चन का भी ध्यान रखना चाहिए और नियमों को आमजन की समस्या को ध्यान रखते हुए लागू करना चाहिए पिछले पांच दिनों से देश के तमाम एयरपोर्ट पर जो दृश्य दिखाई दे रहा है,वह भारतीय विमानन क्षेत्र के लिए एक बड़े संकट का संकेत है वहीं सरकारी स्तर पर बेहद अपरिपक्वता भरे फैसले का नतीजा है। देश की सबसे भरोसेमंद और सफल एयरलाइन मानी जाने वाली इंडिगो अचानक अपने इतिहास के सबसे खराब दौर से गुजर रही है। 2000 से अधिक उड़ानें रद्द होना, कोई साधारण प्रशासनिक गड़बड़ी नहीं, बल्कि एक ऐसी जटिल स्थिति है, जिसने भारत के एविएशन मॉडल की कमियों को उजागर कर दिया है। अगर देखा जाए तो ऑपरेशनल ब्रेकडाउन ने भारत की उड़ान व्यवस्था की विश्वसनीयता, नियामकीय क्षमता और यात्री हितों के प्रति प्रतिबद्धता तीनों को कठोर प्रश्नों के घेरे में ला दिया है। यह संकट सिर्फ एक एयरलाइन की गलती नहीं, बल्कि उस पूरे ढांचे की कमजोरी है जो वर्षों से बढ़ती मांग, सीमित संसाधन और अपर्याप्त नियमन के बीच लड़खड़ा रहा है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि इंडिगो के संकट ने आम यात्रियों की जिंदगी में अकल्पनीय अराजकता ला दी। पांच दिनों में सैकड़ों उड़ानें रद्द होने से यात्रियों को जो जिन दिक्कतों और परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, उसकी सिर्फ कल्पना ही जा सकती है। हजारों यात्री फंसे हुए हैं और एयरपोर्ट किसी रेलवे स्टेशन जैसी भीड़ से भर गए हैं। लोग फर्श पर सोने को मजबूर हैं, खाने-पीने की व्यवस्था नहीं, न होटल, न ईमानदार जानकारी, सब कुछ अव्यवस्थित, थका देने वाला और निराशाजनक सवाल उठता है कि दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था में हमारा एयर ट्रैवल सिस्टम इतनी आसानी से कैसे ढह सकता है? सवाल यह भी है कि क्या सरकार की नीतियों, रेगुलेशन और पायलट रोस्टर नियमों ने मिलकर यह संकट पैदा किया है? सवाल यह है कि आखिर वह एयरलाइन, जिसने भारत के यात्रियों को समय पर उड़ान की आदत डलवाई, वह खुद समय और संचालन दोनों को क्यों मैनेज नहीं कर पा रही ? कंपनी कभी मौसम को जिम्मेदार ठहराती, कभी एयरपोर्ट की भीड़ को, लेकिन वास्तविक चुनौती कहीं गहरे बैठी थी कि कर्मचारी प्रबंधन की कमजोरी और लंबे समय से बढ़ते परिचालन दबाव का ढेर। यह दबाव तव विस्फोटक बन गया जब सरकार के नए एफडीटीएल नियम लागू हुए। यह स्थिति किसी प्राकृतिक आपदा का परिणाम नहीं, बल्कि एक प्रशासनिक और प्रबंधकीय विफलता का परिणाम थी। किसी भी संकट में सबसे पहले शोषण के रास्ते खुलते हैं। इंडिगो की उड़ानें बंद होने के साथ ही अन्य एयरलाइनों ने कुछ रूटों पर टिकट कीमतें सामान्य से 10 गुना तक बढ़ा दीं। टिकटों की दामों में बढ़ोत्तरी ने यात्रियों को परेशानियों को और बढ़ा दिया है। दिल्ली-बेंगलुरु की सबसे सस्ती टिकट 40,000 रुपये से ऊपर दिखाई दी, जबकि कई फ्लाइट्स 80,000 रुपये तक पहुंच गई। यह व्यवहार पूरी तरह गैर-नैतिक था। संकट की घड़ी में लाभ कमाने की यह प्रवृत्ति दिखाती है कि भारतीय विमानन क्षेत्र में मूल्य नियंत्रण की ठोस व्यवस्था अब तक क्यों आवश्यक है। हालांकि सरकार ने बाद में फेयर-कैप लागू कर कीमतें नित्रित कीं, लेकिन यह कार्रवाई शुरुआत से ही की जानी चाहिए थी। देर से जारी नियंत्रण आदेश ने कई यात्रियों को आर्थिक रूप से बुरी तरह प्रभावित किया। हालांकि बाद में इस मामले में नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने दो बड़े आदेश जारी किए किए है। किराया सीमा लागू की गयी है। इसके अलावा प्रभावित यात्रियों से किसी भी प्रकार का री-शेड्यूलिंग शुल्क न लेने का आदेश दिया गया। ये निर्देश बेहद जरूरी थे, पर सवाल यह है कि ऐसी आपात स्थिति में सरकार ने तुरंत हस्तक्षेप क्यों नहीं किया? संकट कई दिनों से बढ़ रहा था, लेकिन मंत्रालय और डीजीसीए की चुप्पी ने हालात को भयावह बनने दिया। किसी भी राष्ट्र में जब यात्रियों का इतना बड़ा संकट उत्पन हो, तो सरकार की जिम्मेदारी होती है कि वह अस्थायी उड़ानें, वैकल्पिक व्यवस्था और मूल्य नियंत्रण तुरंत सुनिश्चित करे। साथ ही समझना होगा कि कि किसी एक कंपनी पर इतनी अधिक निर्भरता स्वयं में एक व्यवस्थागत खतरा है।

वास्तव में भारत का विमानन बाजार पिछले एक दशक में धीरे-धीरे दो बड़ी कंपनियों के बीच सिमटता चला गया है। इंडिगो और एयर इंडिया जब किसी एक कंपनी का बाजार पर इतना बड़ा नियंत्रण हो, तो किसी भी तकनीकी गड़बड़ी, स्टाफ संकट या प्रबंधन विफलता का असर पूरे देश की उड़ान व्यवस्था पर पड़ता है। यह स्थिति उस

'सिंगल पॉइंट ऑफ फेल्योर को दर्शाती है, जिससे खतरा लंबे समय से विशेषज्ञों द्वारा बताया जा रहा है। एविएशन सेफ्टी फर्म मार्टिन कंसल्टिंग के सीईओ मार्क डी मार्टिन के शब्द बेहद मार्मिक हैं कि जिस तरह एडीजीसी ने अपने ही नियमों पर कदम पीछे खींचे, उससे दुनिया को यह संदेश गया है कि भारत की एविएशन रेगुलेशन प्रणाली कमजोर है। जब एक नियामक संस्था किसी एयरलाइन कंपनी के सामने निष्क्रिय दिखती है, तो यह संकेत देता है कि नियमन सिर्फ कागजों में रह गया है। एक मजबूत विमानन देश की पहचान केवल आधुनिक विमानों से नहीं, बल्कि सशक और निष्पक्ष नियामक तंत्र से होती है। 2006 में दिल्ली-मुंबई की उड़ान से शुरू हुई इंडिगो की सफलता कहानी आज भारत के सबसे बड़े विमानन संकटों में से एक के रूप में दर्ज हो रही है। संकट के दौरान मूल्य शोषण रोकने के लिए ऑटोमेटिक फेयर कंट्रोल सिस्टम लागू होना चाहिए। इंडिगो संकट ने भारतीय विमानन क्षेत्र की गहराई तक बैठे संरचनात्मक दोषों को उजागर कर दिया है। यह समय है कि सरकार, एयरलाइंस और नियामक संस्थाएं मिलकर एक ऐसे उड्डयन ढांचे का निर्माण करें जिसमें पारदर्शिता हो, जवाबदेही हो यात्री अधिकार सुरक्षित हों और कोई भी कंपनी इतनी बड़ी न हो जाए कि उसकी गलती से देश का पूरा आकाश ठहर जाए भारत विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती विमानन अर्थव्यवस्थाओं में से एक है। लेकिन विकास केवल तब सार्थक होगा जब वह यात्री कल्याण, मजबूत नियमन और सुव्यवस्थित प्रबंधन के साथ आगे बढ़े। यह संकट एक चेतावनी है कि और यदि इससे सही सीख ली जाए, तो भारतीय विमानन का भविष्य और अधिक सुरक्षित, संवेदनशील और विश्वसनीय बन सकता है। इंडिगो का यह संकट केवल एक एयरलाइन की कहानी नहीं है। यह भारत के विमानन बुनियादी ढांचे, नीतियों, और प्रबंधन की गहरी खामियों का आईना है। भारत विश्व का तीसरा सबसे बड़ा विमानन बाजार बन रहा है। लेकिन अगर नींव कमजोर होगी, तो इस विकास की गति किसी भी दिन रुक सकती है, ठीक वैसे ही जैसे आज इंडिगो के रनवे पर रुक गई है। यात्रियों का भरोसा ही किसी एयरलाइन की सबसे बड़ी पूंजी है। इंडिगो को यह समझना होगा कि लाखों लोग उससे सिर्फ टिकट

नहीं खरीदते, बल्कि वे अपना समय, अपनी योजनाएं और अपनी उम्मीदें भीउस पर भरोसे से छोड़ते हैं। यह संकट एक चेतावनी है कि उसे सुनना इंडिगो के लिए जितना जरूरी है ध्यान रखना होगा कि भविष्य में ऐसी घटना की पुनरावृत्ति न हो।

इंडिगो भारत की सबसे बड़ी एयरलाइन है. स्टैटिस्टा के मुताबिक, साल 2025 के सितंबर महीने तक का डेटा बताता है कि घरेलू उड़ानों में इंडिगो का हिस्सा 63 फीसदी है. दूसरे नंबर पर 13.6 प्रतिशत हिस्सेदारी के साथ एयर इंडिया, इंडिगो से बहुत दूर है, अक्टूबर 2025 तक भारत की घरेलू उड़ानों में लगभग 90 मिलियन यात्रियों ने इंडियो से सफर किया. इस संख्या के साथ बाजार में इंडिगो की हिस्सेदारी 64.5 प्रतिशत है. जहां तक मौजूदा संकट का सवाल है, तो नए नियमों के लिए समय रहते तैयारी ना करके ये दिक्कत इंडिगो ने खुद पैदा कीं.सरकार हवाई यात्रा को अधिक सुरक्षित बनाने के लिए पायलटों के काम करने और आराम करने के घंटों से जुड़े नए नियम लाई. लेकिन इनके क्रियान्वयन के लिए तैयारी नहीं की गयी इससे सरकार के नीति नियंताओ को भी उत्तरदायी होने से बचा नहीं सकते हैं।

मनोज कुमार अग्रवाल

इंडिगो का संकट: एकाधिकार और देश की उड़ान पर खतरा

[विकल्प, प्रतिस्पर्धा और न्याय: अब फैसला हमारे हाथ में]

[टिकट महंगे, सपने टूटे: भारतीय हवाई यात्रा की नग्न सच्चाई]

कभी आसमान आम आदमी का सपना था। आज हवाई यात्रा केवल अमीरों का खेल बन गई है। दिल्ली से चेन्नई का 9 हज़ार का टिकट अचानक 60-80 हज़ार तक पहुँच गया। यह केवल किराया नहीं, यह भारतीय एविएशन की नग्न सच्चाई का उद्घोष है। इंडिगो का हालिया मेल्टडाउन कोई आकस्मिक घटना नहीं; यह उस कमजोर ढांचे की चेतावनी है जिस पर वर्षों तक भरोसा किया गया। जब एक ही कंपनी के पास 63% से अधिक बाज़ार होता है, तो उसकी गड़बड़ी पूरे देश को हिला देती है। सबक साफ है–जब सारा दांव एक घोड़े पर होगा, और वह घोड़ा लंगड़ा हो, तो पूरा देश लंगड़ाएगा।

इंडिगो कभी 'लो-कॉस्ट किंग' थी। आज वही किंग बिना ताज और बिना तैयारी के संकट के बीच नंगा खड़ी है। नया एफडीटीएल (फ्लाइट ड्यूटी टाइम लिमिटेशन) नियम आया–पायलटों को पर्याप्त आराम मिले। यह सही कदम है, लेकिन तैयारी न के बराबर थी। परिणाम भयानक रहा। पायलटों की भारी कमी, क्रू शॉर्टेज और सिस्टम क्रैश ने दिल्ली के मुख्य हब से उड़ानों को रद्द कर दिया। मुंबई में टिकट 48-93 हज़ार और बेंगलुरु में 80-92 हज़ार तक पहुँच गई। एक माँ अपनी बीमार बेटी के साथ दिल्ली नहीं पहुँच पाई। एक स्टार्टअप फाउंडर 2 करोड़ की फंडिंग राउंड चूक गया। यह केवल आंकड़े नहीं; यह टूटते सपनों और जीवन की कहानियाँ हैं।

सच्चाई यह है कि सस्ती उड़ानों का सपना पूरा करने के चक्कर में हमने हवाई यात्रा की रीढ़ ही तोड़ दी। पिछले दो वर्षों में इंडिगो के चालीस से अधिक विमान जमीन अभी भी प्रैट एंड व्हिटनी इंजन की खराबी के कारण ग्राउंडेड हैं। नए विमानों के आदेश में देरी और वैकल्पिक योजना की कमी ने हालात और गंभीर बना दिए। स्पाइसजेट दिवालिया होने की कगार पर है। विस्तारा और एयर इंडिया का विलय 2024 में पूरा हो चुका है, लेकिन एकीकरण प्रक्रिया अभी जारी है। अकासा तेजी से नई उड़ानें शुरू कर रही है, लेकिन अभी उसका प्रभाव सीमित है। परिणाम स्पष्ट है–इंडिगो की एक छींक पूरे क्षेत्र को हिला देती है। यह केवल एकाधिकार नहीं है; यह राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए गंभीर खतरे की चेतावनी है।

सुधार की शुरुआत तभी होगी जब हम एकाधिकार के खतरे को गंभीरता से समझें। टाटा को अपने विमान बेड़े में तेजी से तीन सौ नए विमान शामिल करने की अनुमति दी जानी चाहिए। अकासा को अपने 222 विमानों के मौजूदा ऑर्डर को तेजी से पूरा करने का अवसर मिलना चाहिए। नए निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए फ्लाइट राइट्स को पूंजी बाजार में लाना अनिवार्य है। इससे न केवल प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी, बल्कि यात्रियों के लिए विकल्प और किरायों में स्थिरता भी आएगी।

सिर्फ़ कंपनियों को विस्तार देने से ही काम नहीं चलेगा। हवाई अड्डों के बुनियादी ढांचे पर भी तेज़ी से काम करना अनिवार्य है। जेवर, नवी मुंबई और 2030 तक बनने वाले पचास नए हवाई अड्डे केवल इमारतें नहीं हैं; ये पूरे भारतीय हवाई नेटवर्क की जीवन रेखा हैं। भीड़भाड़ वाले हबों को कम करना, क्षेत्रीय कनेक्टिविटी बढ़ाना और लॉजिस्टिक सिस्टम को मज़बूत करना अब सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए। इससे देशभर में उड़ानों की सुगमता बढ़ेगी और एयरलाइंस के संचालन में स्थिरता सुनिश्चित होगी।

साथ ही, पायलटों की गंभीर और लगातार बढ़ती कमी को तुरंत और प्रभावी ढंग से दूर करना अनिवार्य है। वर्तमान में भारत में लगभग दस-बारह हजार सक्रिय पायलट हैं, जबकि 2030 तक यह संख्या बीस हजार से अधिक होना चाहिए, ताकि देश का घरेलू और अंतरराष्ट्रीय हवाई नेटवर्क सुचारु रूप से संचालित हो सके। इसके लिए नई उड़ान अकादमियाँ खोली जानी चाहिए और मौजूदा प्रशिक्षण क्षमता को कई गुना बढ़ाना होगा। साथ ही, लड़कियों को प्रोत्साहित करने और महिला पायलटों की संख्या बढ़ाने के लिए विशेष कार्यक्रम चलाए जाने चाहिए। यह केवल संख्या का सवाल नहीं है; यह उद्योग की मजबूती और समाज में समान अवसरों की अनिवार्यता का प्रतीक है।

किराया नियंत्रण पर भरोसा करना समाधान नहीं है। आज टिकट साठ-पैंसठ हज़ार इसलिए हैं क्योंकि सप्लाई कम है, मांग नहीं। सप्लाई बढ़ाओ–नए विमान, नई एयरलाइंस, सुचारु संचालन–और किराया अपने आप आठ हज़ार तक नीचे आ जाएगा। यह अर्थशास्त्र का बुनियादी नियम है, जिसे हम भावनाओं और तात्कालिक निर्णयों में भूल चुके हैं। यह संकट दर्द ज़रूर दे रहा है, लेकिन यह शायद आखिरी ऐसा दर्द हो सकता है। अगर सरकार और उद्योग ने आज साहस दिखाया, तो 2027 तक भारत का घरेलू हवाई नेटवर्क दुनिया का सबसे मजबूत, सबसे सस्ता और सबसे विविध नेटवर्क बन सकता है। साठ-अस्सी हज़ार का टिकट हमें यह कटु सच याद दिला रहा है कि आसमान किसी एक कंपनी की जागीर नहीं हो सकता। सस्ती उड़ान का सपना तभी साकार होगा जब उसे किसी एकाधिकार की दया, मनमानी और कमजोरी पर निर्भर न रहने दिया जाए। आकाश किसी एक का नहीं–वह हम सबका अधिकार है, हमारी सामूहिक उम्मीद है। अब फैसला हमारे हाथ में है। या तो हम अपना आसमान वापस छीनकर संतुलित, मजबूत और न्यायपूर्ण व्यवस्था बनाएँ, या फिर हमेशा ज़मीन पर खड़े होकर महँगी उड़ानों के सामने बेबस आँसू बहाते रहें।

प्रो. आरके जैन

मुद्रक, प्रकाशक एवं सम्पादक रवि कुमार अवस्थी द्वारा सुशीला स्टेडी बेल एकेडमी 117-मोहल्ला विजय लक्ष्मी नगर परगना खैराबाद तहसील व जनपद -सीतापुर से प्रकाशित तथा महावीर आफसेट 28, हीवेट रोड लखनऊ से मुद्रित। सम्पादक रवि कुमार अवस्थी समाचार पत्र में छपे समस्त समाचार संवाददाताओं के अपने श्रोत एवं संकलन हैं, जिनसे सम्पादक का सहमत होना आवश्यक नहीं है। **नोट:**-उपरोक्त सभी पद अवैतनिक एवं स्वयंसेवी हैं तथा समाचार पत्र से सम्बंधित सारे विवादो का न्याय क्षेत्र सीतापुर होगा। R.N.I NO. UPHIN/2012/43078 मो0 नं0 -9511151254,E-Mail :- news@swatantraprabhat .com

संक्षिप्त खबरें

दो बाइकों की भिड़ंत, दो युवक गंभीर रूप से घायल

लालगंज (रायबरेली)। कोतवाली क्षेत्र के कानपुर रोड पर भादे मोड़ के पास रविवार को दो बाइकों की टक्कर में दो युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। दुर्घटना के बाद मौके पर मौजूद लोगों ने तुरंत एंबुलेंस बुलाकर घायलों को सीएचसी पहुंचाया, जहां उनका प्राथमिक उपचार किया गया।निराला नगर निवासी 18 वर्षीय रचित निर्मल, पुत्र राकेश, अपने मित्र 15 वर्षीय साहिल, पुत्र कुलदीप निवासी सूदन खेड़ा, के साथ बाइक से सेमरी की ओर जा रहे थे। इसी दौरान आगे चल रही एक दूसरी बाइक ने अचानक मोड़ काट दिया, जिससे उनकी बाइक अनियंत्रित होकर सड़क पर फिसल गई और दोनों युवक घायल हो गए। घटना के बाद दूसरी बाइक पर सवार लोग मौके से फरार हो गए।

मिशन शक्ति अभियान के तहत परिवार परामर्श केंद्र में 03 पारिवारिक विवादों का सफल निस्तारण

बलरामपुर। नारी सुरक्षा, नारी सम्मान और नारी स्वावलंबन के उद्देश्य से चल रहे मिशन शक्ति अभियान 5.0 के अंतर्गत शनिवार को पुलिस अधीक्षक कार्यालय स्थित परिवार परामर्श केंद्र में पारिवारिक विवादों से जुड़े प्रकरणों पर बैठक आयोजित की गई। बैठक में सक्रिय मध्यस्थता और परामर्श के माध्यम से तीन पारिवारिक विवादों का सफल निस्तारण कराया गया। पुलिस अधीक्षक बलरामपुर विकास कुमार के निर्देशन तथा अपर पुलिस अधीक्षक विशाल पाण्डेय के पर्यवेक्षण में आयोजित इस बैठक में पति-पत्नी एवं परिजनों के बीच आपसी सुलह एवं समझौता कराकर दोनों पक्षों को सौहार्दपूर्ण माहौल में आगे जीवन व्यतीत करने की सलाह दी गई। परामर्शदाताओं ने दंपतियों को परस्पर विश्वास, संवाद और सहयोग के साथ जीवन की नई शुरुआत करने पर बल दिया। निस्तारण किए गए मामलों में सादिया खातून बनाम मोहम्मद इरशाद (थाना सादुल्लानगर), मसीउल्लाह बनाम परवेज अहमद (थाना तुलसीपुर) तथा गीतांजलि बनाम मंगल सिंह (थाना तुलसीपुर) प्रमुख रहे।परिवार परामर्श केंद्र में विवादों के समाधान में परामर्शदाता अरुण कुमार यादव, देवतादीन दूबे, वंदना मिश्रा, महिला थाना प्रभारी पूनम यादव तथा महिला कांस्टेबल ज्योति, मनीषा वर्मा और पूजा की विशेष भूमिका रही। बैठक के अंत में दोनों पक्षों ने आपसी मतभेद समाप्त कर सौहार्दपूर्ण वातावरण में साथ रहने की सहमति दी। बलरामपुर पुलिस ने कहा कि पारिवारिक सौहार्द और नारी सम्मान की दिशा में ऐसे प्रयास आगे भी लगातार जारी रहेंगे।

स्वास्थ्य विभाग में तैनात 150 निजी सुरक्षा गार्डों को हटाए जाने से मचा हड़कंप, डीएम आवास पर लगाई गुहार

स्वतंत्र प्रभात संवाददाता

सीतापुर जनपद सीतापुर के स्वास्थ्य विभाग में तैनात 150 निजी सुरक्षा गार्डों को हटाए जाने से हड़कंप मच गया है। ये सभी सुरक्षा गार्ड जीत सिक्योरिटी गार्ड कंपनी के कर्मचारी थे जिनका अनुबंध स्वास्थ्य विभाग के साथ समाप्त होने के बाद यह कार्रवाई की गई अचानक सेवाएं समाप्त होने से गार्डों और उनके परिवारों के सामने रोजी-रोटी का संकट खड़ा हो गया है बताया जा रहा है कि स्वास्थ्य विभाग में तैनात इन सुरक्षा गार्डों की तैनाती जीत सिक्योरिटी कंपनी के माध्यम से की गई थी। कंपनी का अनुबंध अवधि पूरी होने के बाद स्वास्थ्य विभाग ने सेवा समाप्त करने की कार्रवाई शुरू कर दी इस संबंध में मुख्य चिकित्साधिकारी (सीएमओ) द्वारा पत्र जारी कर अनुबंध समाप्त होने की जानकारी दी गई है। शनिवार देर शाम हटाए गए सुरक्षा गार्डों ने एकजुट होकर जिलाधिकारी आवास पहुंचकर अपनी फरियाद रखी गार्डों ने आरोप लगाया कि उन्हें बिना किसी पूर्व सूचना के हटा दिया गया, जिससे वे असमंजस की स्थिति में आ गए हैं। सुरक्षा गार्डों का कहना है कि वे वर्षों से ईमानदारी से अपनी सेवाएं दे रहे थे।

बावजूद इसके उन्हें बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। गार्डों ने जीत सिक्योरिटी कंपनी पर घूस लेकर नियुक्ति करने का भी आरोप लगाया है। उनका कहना है कि कंपनी द्वारा अवैध रूप से उनसे पैसे लेकर नौकरी दी गई थी और अब अनुबंध समाप्त होने के बाद उन्हें बेरोजगार कर दिया गया है हालांकि इन आरोपों पर कंपनी की ओर से कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है सीएमओ डॉ सुरेश कुमार ने बताया कि स्वास्थ्य विभाग में अब पूर्व सैनिक कल्याण समिति के साथ नया अनुबंध किया गया है ऐसे में हटाए गए सुरक्षा गार्डों ने मांग की है कि उन्हें नई कंपनी के अंतर्गत स्थानांतरित किया जाए, जिससे उनके परिवारों की आजीविका बनी रहे जिलाधिकारी से मामले में न्यायोचित निर्णय की उम्मीद सुरक्षा गार्डों ने जताई है!!

जन कल्याण समिति विराम खंड 5 गोमती नगर द्वारा संरक्षक का किया गया शोक सभा

लखनऊ। राजधानी लखनऊ में आज दिश 07 दिसंबर 2025 को विराम खण्ड-5, गोमतीनगर, जनकल्याण समिति द्वारा समिति के संरक्षक रहे। गोरख प्रसाद निषाद, पूर्व पशुधन मंत्री जिनका निधन 28 नवंबर 2025 को हो गया था। उनका दाह संस्कार 29 नवंबर 2025 को सरजू जी में गृह जनपद देवरिया बरहज में किया गया है। उनकी आत्मा की शान्ति और दुखी परिवार को संवेदना व्यक्त करने हेतु आज शोक सभा का आयोजन 'अमर शहीद चंद्र शेखर आज़ाद पार्क' विराम खंड-5 में किया गया। शोक सभा में जनकल्याण उपसमिति विराम - 5 अध्यक्ष, डॉ. भरत राज सिंह, खण्ड प्रभारी राकेश जेतली, एस.बी.एल. मेहरोत्रा, मनोज शर्मा, प्रचार- प्रसार अधिकारी, अधिवक्ता, नित्यानंद पाण्डेय, आर.एन. सिंह, मुख्य प्रचारक, राष्ट्रीय स्वयं सेवक, गोमतीनगर व सम्मानित निवासी गण ने पुष्पांजलि तथा 2 मिनट का मौन रखकर भावभीनी श्रद्धांजली अर्पित की।

प्रशासन ने चलाया अतिक्रमण अभियान छोटे दुकानदारों के हटाए टीनशेड, बड़े प्रतिष्ठानों को दी चेतावनी

स्वतंत्र प्रभात संवाददाता

सीतापुर जनपद सीतापुर में डीएम के आदेशों के बावजूद शहर में चलाया गया अतिक्रमण हटाओ अभियान महज औपचारिकता बनकर रह गया। रविवार दोपहर बाद जीआईसी चौराहे से बस स्टॉप तक चले इस अभियान में प्रशासनिक अधिकारियों की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े हो गए हैं अभियान की कमान एसडीएम सदर और नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी वैभव त्रिपाठी के हाथों में थी लेकिन कार्रवाई देखकर आमजन और व्यापारी वर्ग में आक्रोश देखी गई। अभियान के दौरान बड़े-बड़े भवनों और प्रतिष्ठानों के बाहर सड़कों तक फैले अतिक्रमण को नजरअंदाज कर दिया गया, जबकि छोटे दुकानदारों की टीन शेड और अस्थायी दुकानों पर ही बुलडोजर और हथौड़ा चला इससे यह साफ जाहिर हुआ कि कार्रवाई चयनित और पक्षपातपूर्ण रही सड़कों पर कब्जा किए रसूखदार लोगों को खुली छूट दी गई, जबकि रोजी-रोटी चलाने वाले छोटे व्यापारियों को सबसे पहले निशाना बनाया गया। स्थानीय व्यापारियों का कहना है कि डीएम के निर्देशों का हवाला जरूर दिया गया, लेकिन जमीनी हकीकत इससे उलट नजर आई व्यापारियों का आरोप है कि प्रशासन ने केवल खानापूर्ति के लिए कुछ दुकानों को हटाकर फोटो और रिपोर्ट थाने व उच्चाधिकारियों को भेजने की औपचारिकता निभा ली। इस दौरान कई दुकानदारो के सामने लगे टीनशेड को उखाडकर जब्त कर लिया गया अतिक्रमण अभियान के दौरान कई दुकानदारों में आक्रोश देखने को मिला उनका कहना है कि यदि अतिक्रमण हटाना ही था तो सभी के खिलाफ समान कार्रवाई होनी चाहिए थी!!

लाइब्रेरी व पुस्तकालय का इस युग में होना अति आवश्यक हो गया है:-कोतवाली प्रभारी अरविंद सिंह

स्वतंत्र प्रभात संवाददाता

लहरपुर सीतापुर लाइब्रेरी व पुस्तकालय का इस युग में होना अति आवश्यक हो गया है क्योंकि सोशल मीडिया के इस दौड़ में हम शांति पूर्वक और एकांत वातावरण में अगर पुस्तकों का अध्ययन करेंगे तभी हम प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता अर्जित कर सकेंगे उक्त विचार अरविंद सिंह कोतवाली प्रभारी लहरपुर ने मजाशाह मेंन रोड स्थित लाइब्रेरी के उद्घाटन के मौके पर छात्र एवं छात्रों को संबोधित करते हुए व्यक्त किया उन्होंने छात्रों से बताया कि अनुशासन में रहकर नियमित रूप से पढ़ाई करें और कोई भी ऐसा अनैतिक कार्य न करें जिससे आपको भविष्य में नुकसान हो कार्यक्रम का संचालन सामाजिक कार्यकर्ता मोहम्मद हसीन अंसारी ने किया। कार्यक्रम को हाजी जुनैद अहमद, हाशिम अंसारी, मास्टर आसिफ, जफर ,सलीम आदि लोगों ने संबोधित किया। लाइब्रेरी फाउंडर समिति में अतीक अहमद, मोहम्मद आमिर सर, मोहम्मद सोहराब, मोहम्मद आमिर ने बुके देकर मुख्य अतिथि का स्वागत किया। कार्यक्रम में मुख्य रूप से देवेंद्र सिंह अध्यक्ष सिंह संगठन तहसील लहरपुर, पूर्व सभासद इस्लामुद्दीन, मोहम्मद सलीम, जग्गू, मोहम्मद अयूब, मास्टर वकील, डॉक्टर जीशान, वकील किंग इनवर्टर, मोहम्मद जकी बसर, मोहम्मद आसिफ समेत बड़ी संख्या में अध्यापक एवं छात्र एवं छात्रायें उपस्थित रहे।

रंजिश के चलते भिड़े दो पक्ष, गंभीर चोटें; पुलिस ने शुरू की जांच

लालगंज (रायबरेली)। कोतवाली क्षेत्र के पूरे रामगुलाम मजरा मदुरी गांव में शनिवार देर शाम रंजिश के चलते दो पक्षों के बीच मारपीट हो गई। घटना में दोनों ओर के लोग घायल हो गए। सूचना पर पहुंची पुलिस ने दोनों पक्षों की तहरीर लेकर मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।गांव निवासी मोहित ने आरोप लगाया कि रंजिश के चलते देवेंद्र, राजेंद्र, दीपक, गुड्डू, दीपू, श्रीपाल, धीरेंद्र तथा चार-पांच अज्ञात लोगों ने गाली-गलौज करते हुए उन पर हमला कर दिया, जिससे उन्हें गंभीर चोटें आई। वहीं दूसरे पक्ष से भूपेंद्र ने तहरीर देकर आरोप लगाया कि मोहित, रोहित, दिलीप, पंकज और राम मोहन ने उनके साथ मारपीट की। प्रभारी निरीक्षक प्रमोद कुमार सिंह ने बताया कि दोनों पक्षों के आरोपों के आधार पर मुकदमा दर्ज कर आवश्यक कार्रवाई की जा रही है।

92 हिस्ट्रीशीटरों की थाने में लगी पाठशाला पंचायत चुनाव से पहले अपराध से दूर रहने की दिलाई शपथ

स्वतंत्र प्रभात संवाददाता

सीतापुर जनपद सीतापुर में पंचायत चुनावों की आहट और सर्दी का मौसम शुरू होने के मद्देनज़र बिसवां कोतवाली परिसर में एक अनोखी और सराहनीय पहल देखने को मिली कोतवाली प्रभारी निरीक्षक मुकुल प्रकाश वर्मा की अगुवाई में 92 नामजद हिस्ट्रीशीटरों की 'पाठशाला' लगाई गई, जहां उन्हें कानून का पालन करने और अपराध से दूर रहने का संदेश दिया गया इस दौरान प्रभारी निरीक्षक मुकुल प्रकाश वर्मा ने सभी हिस्ट्रीशीटरों को स्पष्ट शब्दों में चेताया कि चुनावी माहौल और ठंड के मौसम में अपराध की घटनाओं में बढ़ोतरी की आशंका रहती है ऐसे में किसी भी तरह की अवैध गतिविधि बर्दाश्त नहीं की जाएगी। साथ ही उन्होंने सख्त लहजे में कहा कि यदि कोई व्यक्ति पुराने रास्ते छोड़कर सकारात्मक जीवन जीना चाहता है तो पुलिस प्रशासन उसका हरसंभव सहयोग करेगा पाठशाला के दौरान उपस्थित हिस्ट्रीशीटरों ने भी खुलकर अपने मन की बात रखी। कई लोगों ने स्वीकार किया कि उन्होंने अपने बीते जीवन में अपराध किए थे, लेकिन अब वे उस रास्ते को छोड़कर अपने परिवार के साथ शांतिपूर्ण जीवन जी रहे हैं कुछ ने मजदूरी, तो कुछ ने छोटे-मोटे काम कर ईमानदारी से रोजी-रोटी कमाने की बात कही। हिस्ट्रीशीटरों ने यह भी कहा कि अब वे दोबारा किसी अपराध में शामिल नहीं होना चाहते और समाज की मुख्यधारा में रहकर जिंदगी बिताना चाहते हैं कोतवाली प्रभारी ने सभी को अपराध न करने, असामाजिक तत्वों से दूरी बनाए रखने और किसी भी संदिग्ध गतिविधि की जानकारी पुलिस को देने की शपथ दिलाई उन्होंने बताया कि पंचायत चुनाव शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराना पुलिस की प्राथमिकता है और इसमें क्षेत्रवासियों के साथ-साथ इन लोगों की भी अहम भूमिका है कार्यक्रम के अंत में प्रभारी निरीक्षक मुकुल प्रकाश वर्मा ने कहा कि ऐसी पाठशालाओं का उद्देश्य डर पैदा करना नहीं, बल्कि सुधार और पुनर्वास है। पुलिस चाहती है कि हर व्यक्ति कानून का सम्मान करे और समाज में शांति और सौहार्द बना रहे!!

तेज रफ्तार पीआरवी वाहन ने मारी बुजुर्ग महिला को टक्कर, परिजनों का आरोप, गंभीर हालत में महिला लखनऊ रेफर

स्वतंत्र प्रभात संवाददाता

सीतापुर जनपद सीतापुर के थाना तालगांव क्षेत्र के बिलहरी गांव में शनिवार देर रात एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया। खेत से अपने घर लौट रही एक बुजुर्ग महिला को तेज रफ्तार चार पहिया वाहन ने जोरदार टक्कर मार दी, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गई। परिजन और स्थानीय लोगों की मदद से घायल महिला को तत्काल जिला अस्पताल लाया गया जहां प्राथमिक उपचार के बाद हालत नाजुक देखते हुए डॉक्टरों ने उसे लखनऊ रेफर कर दिया। घायल महिला की पहचान राजकुमारी पत्नी जसकरण के रूप में हुई है। बताया गया कि राजकुमारी खेत से काम निपटाकर सड़क पार कर अपने घर जा रही थीं तभी अचानक तेज गति से आए चार पहिया वाहन ने उन्हें टक्कर मार दी टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि बुजुर्ग महिला सड़क पर दूर जाकर गिर पड़ीं और मौके पर ही बेहोश हो गईं आसपास मौजूद ग्रामीणों ने तुरंत परिजनों और पुलिस को घटना की सूचना दी महिला के बेटे अखिलेश ने हादसे को लेकर गंभीर आरोप लगाए हैं।

उनका कहना है कि टक्कर मारने वाला वाहन डायल 112 पुलिस वाहन था जो घटना के बाद मौके से फरार हो गया अखिलेश का आरोप है कि यदि समय रहते वाहन रुककर घायल को अस्पताल पहुंचाया जाता तो स्थिति इतनी गंभीर नहीं होती परिजनों का कहना है कि पुलिस वाहन की पहचान होते हुए भी अब तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। वहीं, घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। पुलिस का कहना है कि आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली जा रही है और प्रत्यक्षदर्शियों से पूछताछ की जा रही है। पुलिस ने आश्वासन दिया है कि जांच के बाद दोषी वाहन चालक के खिलाफ विधिक कार्रवाई की जाएगी!!

इनर व्हील क्लब द्वारा महिलाओं के विरुद्ध होने वाली हिंसा के प्रति जागरूकता फैलाने हेतु निकली गई रैली

स्वतंत्र प्रभात संवाददाता

बिसवां/सीतापुर इनर व्हील क्लब बिसवां द्वारा महिलाओं के विरुद्ध होने वाली हिंसा के प्रति जागरूकता फैलाने हेतु आज एक प्रभावशाली रैली का सफलतापूर्वक आयोजन किया गया। इस रैली का उद्देश्य समाज में महिलाओं की सुरक्षा, सम्मान और अधिकारों के प्रति जागरूकता बढ़ाना तथा हिंसा के खिलाफ आवाज उठाना था। रैली के साथ-साथ पोस्टर प्रतियोगिता भी आयोजित की गई, जिसमें प्रधानाचार्या श्रीमती अल्पना अवस्थी के सानिध्य में कृष्ण स्वरूप अग्रवाल सरस्वती बालिका विद्या मन्दिर इन्टर कॉलेज अमर नगर बिसवां विद्यालय की छात्राओं ने अपने रचनात्मक और सार्थक संदेशों के माध्यम से महिलाओं की सुरक्षा के मुद्दों को बेहद प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत किया।

कार्यक्रम विशेष आकर्षण रहा नुक्कड़ नाटक, के माध्यम से विद्यालय की छात्राओं ने विभिन्न प्रदर्शन प्रस्तुत किये। नाटक में महिलाओं के प्रति बढ़ती हिंसा, सामाजिक कुरीतियाँ और आत्मनिर्भरता का संदेश अत्यंत भावनात्मक और प्रेरणादायी शैली में दर्शाया गया, जिसे उपस्थित सभी लोगों ने सराहा। कार्यक्रम में इनर व्हील क्लब की अनेक सक्रिय सदस्यगण कोऑर्डिनेटर गुंजन सेठ, कोऑर्डिनेटर रेनू मेहरोत्रा, अंजली राजवंशी, सुनीता अग्रवाल, निधि सिंघल, ऋचा गुप्ता और मीरा सिंघल–की उपस्थिति ने कार्यक्रम को और भी सशक्त बनाया। सभी सदस्यों ने मिलकर यह संदेश दिया कि एक सुरक्षित समाज का निर्माण तभी संभव है जब हम सब मिलकर महिलाओं के प्रति संवेदनशीलता और सम्मान की भावना को बढ़ावा दें। अध्यक्षा गुरमीत कौर व सचिव तुलसी गुप्ता ने कार्यक्रम की सफलता पर खुशी व्यक्त करते हुए सभी सदस्यों, छात्राओं और विद्यालय के शिक्षक- स्टाफ का धन्यवाद किया।

जेवरों संग लापता हुई महिला और बेटी, सीएम हस्तक्षेप पर पुलिस हरकत में

लालगंज (रायबरेली)। कस्बे के महेशनगर मोहल्ला निवासी एक रिक्शा चालक की पत्नी अपनी बेटी और कीमती जेवरों के साथ अचानक लापता हो गई। पीड़ित पति ने कई बार गुहार लगाने के बाद भी पुलिस द्वारा कार्रवाई न किए जाने पर मामला मुख्यमंत्री कार्यालय तक पहुंचाया, जिसके बाद पुलिस हरकत में आई और दो महिलाओं समेत तीन लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।सरैनी थाना क्षेत्र के चंदू का पुरवा गांव निवासी दिनेश अपनी पत्नी और बेटी के साथ महेशनगर मोहल्ले में किराए के मकान में रहता है। वह रिक्शा चलाकर परिवार का भरण-पोषण करता है। पीड़ित के अनुसार 24 सितंबर की शाम करीब 6 बजे उसकी पत्नी बेटी के साथ घर से निकली और मंगलसूत्र, कानों के झुमके, पायल, करधनी समेत कई कीमती जेवर लेकर एक अज्ञात व्यक्ति के साथ चली गई। परिजन और दिनेश ने काफी खोजबीन की, लेकिन दोनों का कोई पता नहीं चला।कई बार थाना पुलिस से शिकायत करने के बाद भी कार्रवाई न होने पर दिनेश ने मुख्यमंत्री से न्याय की गुहार लगाई। सीएम कार्यालय ने मामले में तत्काल जांच करने के निर्देश दिए। प्रभारी निरीक्षक प्रमोद कुमार सिंह ने बताया कि दो महिलाओं सहित एक अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। पुलिस लापता महिला एवं उसकी बेटी की तलाश में लगातार दबिश दे रही है।

एसडीआरएफ और पुलिस की दमदार कार्रवाई: 36 घंटे बाद पोखरे से बरामद हुआ युवक का शव

स्वतंत्र प्रभात संवाददाता

सहजनवां- गोरखपुर; सहजनवां थाना क्षेत्र के टड़वा खुर्द गांव में शुक्रवार दोपहर एक दर्दनाक हादसा सामने आया, जहां पोखरे में स्नान करने गए युवक की डूबकर मौत हो गई। घटना के बाद से ही स्थानीय पुलिस और एसडीआरएफ की टीमें युवक की तलाश में जुटी थीं, लेकिन पोखरे की गहराई और कीचड़ के कारण रेस्क्यू बेहद चुनौतीपूर्ण हो गया था। लगभग 36 घंटे की अथक मशक्कत के बाद रविवार को युवक का शव पोखरे से बरामद कर लिया गया।

जानकारी के अनुसार, मृतक सोनू राजभर (22) पुत्र परमहंस राजभर, निवासी मतवलिया थाना रामकोला, जनपद कुशीनगर, गुरुवार को अपने पड़ोसी गांव टड़वा खुर्द अपने मित्र महेंद्र कुशवाहा से मिलने आया था। महेंद्र गांव के एक व्यक्ति के यहां पाइप बनाने का काम करता है। शुक्रवार दोपहर करीब दो बजे सोनू पास के पोखरे में स्नान करने गया, लेकिन कुछ ही देर में वह गहरे पानी में चला गया और डूबने से उसकी मौत हो गई।

घटना की सूचना मिलते ही एसडीआरएफ टीम ने शुक्रवार शाम से ही पोखरे में तलाशी अभियान शुरू कर दिया, लेकिन पानी की अधिकता, कीचड़ और पोखरे की गहराई के कारण शव का पता नहीं चल सका। स्थिति को देखते हुए थानेदार सहजनवां महेश कुमार चौबे ने रविवार सुबह पोखरे से पानी निकालने की व्यवस्था कराई। जैसे ही पानी का स्तर कम होना शुरू हुआ, शव सतह पर उतराने लगा। एसडीआरएफ टीम ने तुरंत शव को बाहर निकालकर पुलिस के सुपुर्द कर दिया।

लगातार 36 घंटे चले इस रेस्क्यू अभियान में पुलिस, एसडीआरएफ और स्थानीय लोगों की सक्रिय भूमिका रही। मौके पर मौजूद ग्रामीणों ने पुलिस के प्रयासों की सराहना की। थानेदार महेश कुमार चौबे ने बताया कि शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। रिपोर्ट आने के बाद आगे की कार्रवाई नियमानुसार की जाएगी। इस घटना से पूरे क्षेत्र में शोक की लहर है। ग्रामीणों ने पोखरों और जलस्रोतों के पास सुरक्षा इंतजाम बढ़ाने की मांग करते हुए कहा कि यदि समय रहते सतर्कता बरती जाती तो शायद इस तरह की घटना रोकी जा सकती थी।

हजारों किसानों की सहभागिता, से सुशीला वर्मा बनीं महिला मोर्चा मण्डल अध्यक्ष

● ... गौंदा मुआज्जम नगर में भाकियू (भानु) का भव्य संगठन विस्तार कार्यक्रम सम्पन्न।

स्वतंत्र प्रभात संवाददाता

मलिहाबाद (लखनऊ)। मलिहाबाद क्षेत्र के ग्राम गौंदा मुआज्जम नगर में आज भारतीय किसान यूनियन (भानु) द्वारा भव्य संगठन विस्तार कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें क्षेत्र के विभिन्न गांवों से आए हजारों किसानों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। कार्यक्रम का उद्देश्य किसानों को संगठित कर उनके अधिकारों, समस्याओं एवं हितों के लिए एक मजबूत मंच प्रदान करना रहा।

कार्यक्रम के दौरान श्रीमती सुशीला वर्मा जी ने महिला मोर्चा की मण्डल अध्यक्ष पद की सदस्यता ग्रहण की। उन्हें यह महत्वपूर्ण जिम्मेदारी महिला मण्डल अध्यक्ष, लखनऊ श्री ऋषि मिश्रा जी द्वारा विधिवत रूप से दिलाई गई। इस अवसर पर उपस्थित किसानों व पदाधिकारियों ने तालियों की गड़गड़ाहट के साथ उनका स्वागत कर उन्हें शुभकामनाएं दीं।

कार्यक्रम में जिला अध्यक्ष श्री शिवनारायण शर्मा जी एवं जिला महामंत्री श्री अनूप मौर्य जी की गरिमामयी उपस्थिति विशेष रूप से रही। इनके साथ प्रदेश पदाधिकारी श्री असीम उर्फ शीबू, तहसील महामंत्री मलिहाबाद श्री नफीस अहमद, तहसील उपाध्यक्ष मलिहाबाद, सहित जिला, तहसील एवं ब्लॉक स्तर के अनेक पदाधिकारी मंच पर मौजूद रहे।

अपने संबोधन में वक्ताओं ने कहा कि किसानों की समस्याओं का स्थायी समाधान तभी संभव है जब किसान संगठित होकर अपनी आवाज बुलंद करें। भाकियू (भानु) सदैव किसानों के हक की लड़ाई सड़क से लेकर शासन-प्रशासन तक मजबूती से लड़ती रही है और आगे भी पूरी ताकत के साथ किसानों के हितों की रक्षा करती रहेगी। महिला शक्ति की सक्रिय सहभागिता से संगठन को और अधिक मजबूती मिलेगी। कार्यक्रम का समापन किसान एकता, संगठन की मजबूती और अधिकारों की रक्षा के संकल्प के साथ किया गया। अंत में आयोजकों ने सभी पदाधिकारियों, कार्यकर्ताओं एवं भारी संख्या में उपस्थित किसानों के प्रति आभार व्यक्त किया।

लखनऊ में राष्ट्रीय पत्रकार सुरक्षा परिषद की बैठक संपन्न, पत्रकार सुरक्षा और संगठन विस्तार पर हुई व्यापक चर्चा

● ....दुर्गेश सिंह 'दीपु' बने प्रदेश उपाध्यक्ष, लखनऊ इकाई के कई पदों पर नई जिम्मेदारियाँ; फील्ड में काम करने वाले पत्रकारों की समस्याओं पर संगठन गंभीर।

स्वतंत्र प्रभात संवाददाता

लखनऊ। राष्ट्रीय पत्रकार सुरक्षा परिषद (रजि.) - उत्तर प्रदेश की लखनऊ जिला इकाई की महत्वपूर्ण बैठक रविवार को प्रदेश कार्यालय, वृंदावन योजना सेक्टर-6 (पीजीआई क्षेत्र) में आयोजित की गई, जिसमें जिले के वरिष्ठ एवं युवा पत्रकारों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। कार्यक्रम का शुभारंभ परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री देवेंद्र मिश्रा द्वारा माँ सरस्वती के चित्र पर पुष्पांजलि एवं दीप प्रज्वलन के साथ किया गया। बैठक में पत्रकार सुरक्षा, संगठन विस्तार और फील्ड में कार्यरत पत्रकारों की चुनौतियों पर विस्तृत विमर्श किया गया। राष्ट्रीय अध्यक्ष देवेंद्र मिश्रा ने बताया कि पत्रकार लोकतंत्र के सशक्त प्रहरी हैं, लेकिन जमीनी स्तर पर काम करने वाले पत्रकार कई प्रकार के जोखिम और कठिनाइयों का सामना करते हैं। परिषद का उद्देश्य पत्रकारों को सुरक्षा, सम्मान और आवश्यक सहयोग प्रदान करना है। उन्होंने यह भी बताया कि संगठन प्रदेश के प्रत्येक जिले में सक्रिय रूप से कार्य करते हुए पत्रकारों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम, कानूनी सहायता शिविर व जागरूकता अभियानों को आगे बढ़ाएगा।

बैठक के दौरान संगठन विस्तार के क्रम में परिषद ने दुर्गेश सिंह 'दीपु' को उत्तर प्रदेश का प्रदेश उपाध्यक्ष नियुक्त करने की घोषणा की, जिसका उपस्थित सदस्यों ने तालियां बजाकर स्वागत किया। इसी क्रम में जिले के संगठन में नई जिम्मेदारियों के तहत राजू मोहन पांडे को महासचिव, श्यामलाल गौतम को संगठन मंत्री, आशीष पाल को आईटी सेल में तथा भारत भूषण को उपाध्यक्ष का दायित्व सौंपा गया। राष्ट्रीय अध्यक्ष ने भरोसा जताया कि नई टीम संगठन को नई ऊर्जा और गति प्रदान करेगी।

बैठक में जिले के कई पत्रकारों ने अपने कार्यक्षेत्र में आने वाली समस्याओं को साझा किया, जिनमें थानों में सहयोग की कमी, समाचार संकलन के दौरान उत्पीड़न, ग्रामीण क्षेत्रों में असुरक्षा, पहचान पत्र सत्यापन और प्रशासनिक स्तर पर संवाद की कमी जैसे मुद्दे शामिल रहे। परिषद ने इन सभी बिंदुओं पर गंभीरता व्यक्त करते हुए जल्द ही संबंधित अधिकारियों से वार्ता कर समाधान सुनिश्चित कराने का आश्वासन दिया। बैठक में जिलाध्यक्ष दिलीप मिश्रा, जिला प्रभारी रघुनाथ सिंह, मुकेश द्विवेदी, गौरव शुक्ला, दिव्यांशु त्रिपाठी, अवनीश पांडे, पुष्प राज सिंह, शिवा मिश्रा, रोहित दीक्षित, विनीत मिश्रा, हरिओम दीक्षित, अमन द्विवेदी सहित लखनऊ जनपद के अनेक पत्रकार उपस्थित रहे। सभी सदस्यों ने सामूहिक रूप से यह संकल्प लिया कि पत्रकार हितों और सुरक्षा के लिए परिषद प्रदेशभर में अभियान चलाते हुए संगठन को गांव एवं तहसील स्तर तक विस्तारित करेगी।

संक्षिप्त खबरें

आईआईसीटी एलुमनाई मीट वापी चैप्टर में पूर्व छात्रों का मिलन

भदोही। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कार्पेट टेक्नोलॉजी के पूर्व छात्र शनिवार को अतुल लिमिटेड में आयोजित एलुमनाई मीट में एकत्र हुए। कार्यक्रम का आयोजन संस्थान के निदेशक डॉ. आर.के. वार्ष्णेय के मार्गदर्शन में किया गया। मीट में पूर्व छात्रों ने न केवल पुरानी यादों को ताज़ा किया, बल्कि अपने व्यावसायिक अनुभवों और उपलब्धियों को भी साझा किया। संबोधन में डॉ. वार्ष्णेय ने आईआइसीटी में हो रहे हालिया विकासों की जानकारी दी और एलुमनाई नेटवर्क को मजबूत बनाने के लिए नियमित रूप से ऐसे आयोजन किए जाने की आवश्यकता पर बल दिया।

कार्यक्रम में 2008 से 2025 बैच के लगभग 50 पूर्व छात्र शामिल हुए। इस दौरान प्रदीप शुक्ला (2008), मुनेंद्र सिंह (2009), अनूप चौरसिया (2010), विशाल मिश्रा (2013), अभिषेक श्रीवास्तव और दीपक ने अपने सुझाव और अनुभव प्रस्तुत किए। पाँच पूर्व छात्र अपने परिवारों के साथ पहुँचे, जिससे कार्यक्रम का माहौल और भी आत्मीय हो गया। डॉ. वार्ष्णेय ने वेल्सपन लिविंग लिमिटेड और अतुल लिमिटेड का दौरा कर उद्योग शिक्षा सहयोग को मजबूत करने और भविष्य की संभावनाओं पर चर्चा की। एलुमनाई मीट के आयोजन में अभिषेक, निकेत और सुमित की अहम भूमिका रही। पूरे कार्यक्रम का समन्वय श्री बी.सी. रे के मार्गदर्शन में किया गया।

यूपी में स्मार्ट प्रीपेड मीटर उपभोक्ताओं के पोल से नहीं कटेंगे कनेक्शन, ऑटोमैटिक होगा बदलाव

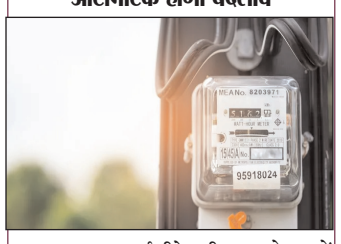

लखनऊ। स्मार्ट प्रीपेड मीटर उपभोक्ताओं का कनेक्शन किसी भी स्थिति में पोल से नहीं काटा जाएगा। पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम के निदेशक (तकनीकी) ने पोल से लाइन उतारने या कनेक्शन काटने पर प्रतिबंध लगा दिया है। स्मार्ट मीटर से जुड़े सभी कनेक्शन ऑटोमैटिक ऑनलाइन प्रणाली से ही कटेंगे या जुड़ेंगे। उन्होंने अभियंताओं और फील्ड स्टाफ के लिए स्मार्ट मीटरिंग सिस्टम पर विशेष प्रशिक्षण अनिवार्य करने के भी निर्देश दिए हैं। राज्य उपभोक्ता परिषद के अध्यक्ष अवधेश कुमार वर्मा के अनुसार स्मार्ट प्रीपेड मीटर के बावजूद प्रदेश में 4702 उपभोक्ताओं के कनेक्शन पोल से काटे गए। यह वही पुरानी व्यवस्था है, जिसमें बिजली कर्मचारी सीढ़ी लेकर पोल पर चढ़कर कनेक्शन काटते थे। जब यह मामला विद्युत निगम के अधिकारियों के संज्ञान में आया तो उन्होंने सभी अभियंताओं और कर्मचारियों को निर्देश दिए कि स्मार्ट प्रीपेड मीटर में किसी भी प्रकार का पोल से कनेक्शन काटना पूर्णतः अनुचित और गैरजरूरी है। प्रदेश में अब तक लगभग 53 लाख स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाए जा चुके हैं। यह मीटर ऑटोमैटिक हैं। इनमें उपभोक्ता के खाते में शेष राशि कम होने या बकाया होने पर बिजली आपूर्ति स्वतः ही रुक जाती है। रिचार्ज होने पर बिजली आपूर्ति शुरू भी हो जाती है, लेकिन कुछ खंडों में अभी भी अभियंता बकाए पर कनेक्शन सीढ़ी से काट रहे हैं।

दिल्ली में सांस लेना मुश्किलः दिसंबर के पहले सप्ताह मे AQI रहा गंभीर, प्रदूषण पर हवा का भी नहीं पड़ा असर

नई दिल्ली। हवा चलने के बाद भी रविवार को दिल्ली की हवा बहुत खराब श्रेणी में रही। शनिवार की तुलना में वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) में कुछ कमी तो आई है, लेकिन अभी भी 300 के ऊपर है। पूरे सप्ताह राजधानी में एक्यूआई बहुत खराब श्रेणी में रहा। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) के आंकड़ों के अनुसार पांच नवंबर के बाद 1 दिसंबर को आइक्यूआइ 300 के नीचे आया था,लेकिन उसके अगले दिन से दोबारा बहुत खराब श्रेणी में पहुंच गया। सीपीसीबी के समीर एप के अनुसार, रविवार को बवाना में सबसे अधिक एक्यूआई 366 और मुंडका में 363 दर्ज किया गया। दिल्ली के 40 निगरानी केंद्रों में से 29 ने वायु गुणवत्ता को बहुत खराब श्रेणी में और 11 ने खराब श्रेणी में बताया। बहुत खराब वायु गुणवत्ता वाले स्टेशनों में पुसा (360), नेहरू नगर (354), रोहिणी (353), जहांगीरपुरी (348), विवेक विहार (348), वजीरपुर (346), आनंद विहार (344), आरके पुरम (336), पंजाबी बाग (328), अशोक विहार (327) और आइटीओ (321) भी शामिल हैं। आईजीआई एयोरपोर्ट पर सबसे कम प्रदूषण रहा। यहां का एक्यूआइ 222 दर्ज हुआ। आइआइटीएम-पुणे के डिसीजन सपोर्ट सिस्टम (डीएसएस) के अनुसार राजधानी के प्रदूषण में सबसे अधिक हिस्सेदारी वाहनों से होने वाले उत्सर्जन की है। पूरे सप्ताह यह लगभग 15% रहा। इसके बाद दिल्ली और आसपास के क्षेत्रों में स्थित औद्योगिक इकाइयों का लगभग7%, आवासीय स्रोत का 3.5% और निर्माण का 2% रहा।

दुष्कर्म के आरोपी ने कुछ ही घण्टों बाद फंदा लगाकर की आत्महत्या

स्वतंत्र प्रभात संवाददाता

हमीरपुर- बिवांर थाना क्षेत्र के उमरी गांव निवासी युवक ने किशोरी के साथ दुष्कर्म करने के बाद फंदा लगाकर खुद मौत को गले लगा लिया। बीते शनिवार शाम लगभग आठ बजे थाना क्षेत्र के उमरी गांव ने किशोरी के साथ दुष्कर्म की घटना हुई। गांव की एक महिला ने पड़ोसी युवक पर अपनी दस साल की पुत्री के साथ दुष्कर्म करने का आरोप लगाते हुए बिवांर थाना में तहरीर दी।पुलिस ने आरोपी आलोक उर्फ सतीश प्रजापति(27)पुत्र रामआसरे के खिलाफ देर रात लगभग एक बजे किशोरी से दुष्कर्म की धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया।लेकिन घटना में उस समय नया मोड़ आ गया जब आरोपी को ढूंढ रही पुलिस को सुबह लगभग साढ़े सात बजे आरोपी का शव उमरी गांव के बाहर नहर पुलिया से कुछ दूर खेत पर खड़े नीम के पेड़ से आरोपी का शव लटका मिला।ग्रामप्रधान कपिल वर्मा ने बताया कि खेत गए लोगों ने देखकर उन्हें सूचना दी ,जिसपर प्रधान ने पुलिस को जानकारी दी।

घटना स्थल में मौदहा सीओ राजकुमार पांडेय ने भी जाकर निरीक्षण किया ,उसके बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया।

पुलिस के मुताबिक ग्रामीणों से जानकारी मिली है कि आरोपी मृतक पहले भी छेड़छाड़ की घटना कर चुका था लेकिन मामले आपसी तौर पर निबटा लिए गए थे।

थाना प्रभारी नन्दराम ने बताया कि सूचना मिलने पर घटना स्थल जाकर देखा गया तो आरोपी का शव नीम के पेड़ से मजार आदि पर चढ़ाई जाने वाली नीले रंग की चादर से बंधा लटका मिला।कहा घटना में अगर कोई दूसरा एंगल मिला तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद स्पष्ट हो सकेगा।बताया प्रथम दृष्टया युवक ने आत्मग्लानि और कानून के भय से यह कदम उठाया होगा।

इनसेटः- गांव के लोगों ने बताया कि आरोपी युवक पहले भी ऐसी तीन वारदात कर चुका था।वहीं पीड़ित किशोरी के पिता ने बताया कि शाम लगभग साढ़े सात बजे आरोपी युवक ने उसकी पुत्री को घर जाकर लोटा देने के लिए कहा और खुद पीछे-पीछे है पहुंचा। बताया कि बच्ची को उठाकर गांव के बाहर खेतों पर ले गया और उसके साथ कुकर्म कर डाला। दूर खेतों में किसानों ने आवाज सुनकर टॉर्च लगाई तो वह भाग गया।बच्ची ने रोते-बिलखते सब कुछ बताया।वहीं बच्ची को ढूंढते-ढूंढते परिजन भी वहां पहुंच गए और बिवांर थाना आकर रिपोर्ट दर्ज कराई।

कप्तानगंज थाने पर शव को रखकर परिजनों ने किया प्रदर्शनकर स्कूल बहन के खिलाफ दर्ज हो मुकदमा

● पीड़ित परिजनों ने स्कूल वाहन चालक के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की कर रहे थे मांगस्कूल वाहन की चपेट में आने से बुजुर्ग व्यक्ति की हुई थी मौत

स्वतंत्र प्रभात संवाददाता

बस्ती। बस्ती जिले के कप्तानगंज थाने पर शव को रखकर पीड़ित परिजनों ने धरना प्रदर्शन किया । पीड़ित परिजनों का आरोप था कि स्कूल वाहन चालक के खिलाफ सन्तोषजनक कार्यवाही नही की गई है सन्तोषजनक कार्यवाही करने की मांग पर पीड़ित परिजन डटे रहे । मामला तूल पकड़ता देख प्रभारी निरीक्षक आलोक कुमार श्रीवास्तव ने पीड़ित परिजनों को समझा बुझाकर धरना प्रदर्शन खत्म कराया और निष्पक्ष जांच कर कार्यवाही करने का आश्वासन दिया।

आपको बता दें कि कप्तानगंज थाना के सामने थाना रोड पर डाक घर के पास तेज रफ्तार स्कूल वाहन ने घर जा रहे बुजुर्ग को

मारी ठोकर मार दी हादसे में कप्तानगंज थाना क्षेत्र के जसईपुर गांव निवासी रामफेर (50) पुत्र गौरी शंकर की मौके पर ही मौत हो गई थी। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया था और मामले की जांच पड़ताल में जुट गई थी। पीड़ित परिजन आज पोस्टमार्टम कराने के बाद शव को लेकर थाने पर पहुंच कर हंगामा किया था। पीड़ित परिवार ने बताया कि जब वाहन को कप्तानगंज पुलिस ने अपने कब्जे में लिया है तो क्यों अज्ञात वाहन के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। अज्ञात वाहन के बजाए ज्ञात वाहन के नाम मुकदमा दर्ज किया जाए। उक्त प्रकरण में सी ओ कलवारी से फोन के माध्यम से जानकारी लेना चाहा तो सी ओ कलवारी का फोन नेटवर्क क्षेत्र से बाहर निकला।

'प्रदूषण की समस्या के लिए पूर्व की सरकारों को दोषी ठहराना अनुचित', रेखा गुप्ता पर भड़के कांग्रेस नेता देवेंद्र यादव

नई दिल्ली। दिल्ली प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष देवेंद्र यादव ने कहा कि मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता का प्रदूषण की समस्या के लिए पूर्व की सरकारों को दोषी ठहराना अनुचित है। वह अपनी जिम्मेदारी से भाग रही हैं। पिछले 10 महीनों में प्रदूषण रोकथाम के लिए भाजपा सरकार द्वारा किए गए काम सिर्फ दिखावा है। उन्होंने कहा कि 2014 से केंद्र में भाजपा के नेतृत्व वाली सरकार है। वर्ष 2007 से 2022 तक दिल्ली नगर निगम में भी भाजपा का शासन था। पिछले 10 महीनों से दिल्ली सरकार और आठ माह से निगम में भाजपा है। इसके बावजूद प्रदूषण की समस्या कम नहीं हुई। दिल्ली में कई काम केंद्र के नियंत्रण में है। धूल व गंदगी हटाने का काम निगम है। उन्होंने कहा कि यदि मुख्यमंत्री यह कह रही हैं कि उन्हें दिल्ली में प्रदूषण की समस्या विरासत में मिली है तो यह भाजपा की भी विफलता है, क्योंकि केंद्र व निगम ने कोई ठोस कदम नहीं उठाया। भाजपा ने सत्ता में आने पर प्रदूषण की समस्या हल करने का वादा किया था। अब मुख्यमंत्री असंवेदनशील बयान देकर अपनी जिम्मेदारी से भाग रही हैं।

धर्मनगरी में संचालित होटलों में पर्यटकों को मिलें अच्छी सुविधाएं- डीएम

स्वतंत्र प्रभात संवाददाता

चित्रकूटः जनपद में संचालित होटलों में मिलेट्स से सम्बन्धी खाद्य उत्पाद, अग्निशमन संबंधी व्यवस्थाएं, स्वीकृत मानचित्र के अनुसार निर्माण के सम्बन्ध में रविवार को कलेक्टरेट सभागार में जिलाधिकारी पुलकित गर्ग की अध्यक्षता में बैठक आयोजित की गई। बैठक में जिलाधिकारी ने कहा कि यहां पर पर्यटन की अपार संभावनाएं हैं, जनपद में बड़ी संख्या में पर्यटक आते हैं। जनपद में संचालित होटल में यदि मूलभूत सुविधायें जैसे साफ-सफाई, पीने का पानी पार्किंग आदि की व्यवस्थाएं सुदृढ़ की जायें तो न केवल जनपद की अलग पहचान बनायी जा सकती है बल्कि होटल व्यवसायी के रूप में अपनी आय को भी बढ़ाया जा सकता है। डीएम ने होटल व्यवसायियों के समक्ष प्रमुख रूप से बुन्देलखण्डी उत्पाद को बढ़ावा देने तथा पर्यटन की दृष्टि से महत्वपूर्ण जनपद चित्रकूट में एकरूपता लाने पर बल दिया। कहा कि अपने शहर की समृद्धि के लिये कार्य करें तथा प्रमुखता से अपने होटल की साफ-सफाई की व्यवस्था कराना सुनिश्चित करें। होटलों में प्लास्टिक की बोतलें रखना बंद करें, उनकी जगह काँच की बोतलों का प्रयोग करें। साफ-सफाई की स्थिति में सुधार लाया जाना अतिआवश्यक है। होटल परिसर में पार्क झूले आदि लगवाकर पर्यटकों को आकर्षित किया जा सकता हैं। कहा कि प्लॉस्टिक उत्पादों के प्रयोग को हतोत्साहित करें तथा होटल में उपलब्ध कराये जाने वाली सामग्री जैसे टूथपेस्ट, साबुन आदि के लिये कागज की बनी थैलियों का प्रयोग करें। कहा कि समस्त होटल व्यवसायी नगर पालिका से समन्वय रखते हुये सूखा एवं गीला कूड़ा नियमित रूप से डिस्पोज करें। गीले कूडे के सम्बन्ध में कहा कि उसकी खाद बनाकर खेतों या पार्क में प्रयोग करें अथवा बिक्री कर मुनाफा कमा सकते हैं। कहा कि कोई भी कूड़ा अपने आस-पास की खुली जगह, मार्गो अथवा सड़को पर नहीं फेंकें।

कहा कि चित्रकूट विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण के अन्तर्गत स्थित समस्त होटल स्वीकृत मानचित्र के अनुसार ही होटल का संचालन करेंगें। कोई भी होटल अथवा व्यवसायिक प्रतिष्ठान यदि आवासीय

मानचित्र स्वीकृत कराकर व्यवसायिक प्रतिष्ठान संचालित कर रहा है, तो उसे दो माह का समय प्रदान किया जा रहा है कि वह अपने व्यवसायिक प्रतिष्ठान के अनुरूप नियमानुसार मानचित्र संशोधित करा ले, अन्यथा की दशा में उसके विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही अमल में लायी जायेगी। चित्रकूट विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण के अधिकारियों व कर्मचारियों को निर्देशित किया कि समस्त मानचित्र स्वीकृत की कार्यवाही अभियान चलाकर पूर्ण की जाये। प्रभारी अग्निशमन अधिकारी को निर्देशित किया गया कि समस्त होटलों में आग से बचाव से सम्बन्धित उपकरण अनिवार्य रूप से लगे होने चाहिये, जिससे किसी भी अप्रिय घटना से बचा जा सके। निर्देशित किया कि समय-समय पर अग्निशमन संयंत्रों का निरीक्षण कर होटल व्यवसायियों को फायर इक्विपमेंट्स चलाने तथा मॉक ड्रिल आदि कराएं। मुख्य खाद्य सुरक्षा अधिकारी को निर्देशित किया कि समस्त होटल में खाद्य सुरक्षा के मानक के अनुरूप ही खाद्य पदार्थ उपलब्ध हों, इसका समय-समय पर निरीक्षण कर व्यवस्थायें सुनिश्चित करायें तथा मिलेट्स उत्पाद को बढ़ावा देने के लिए अपने स्तर से प्रभावी कार्यवाही के लिए कार्ययोजना तैयार करें। चित्रकूट क्षेत्र विकास प्राधिकरण के सचिव को निर्देशित किया गया कि समस्त होटल संचालकों का एक व्हाट्सऐप्प ग्रुप बनाएं। जिससे समय-समय पर शासन के निर्देशों को उन तक पहुँचाने तथा होटल व्यवसायियों के सुझावों का ससमय संज्ञान लिया जा सके।

सभी होटल व्यवसायिकों से कहा कि जनपद की अपनी एक अलग पहचान होनी चाहिये। इस परम्परा को अपनाते हुये सभी होटल परिसर में स्थानीय कलाकृतियों को प्रदर्शित करें। सम्पूर्ण रामघाट में स्थित होटल व व्यवसायिक प्रतिष्ठानों के निर्माण में एकरूपता बनायी जाये, जिससे जनपद चित्रकूट की एक अलग पहचान बन सके। विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण सचिव को निर्देशित किया कि रामघाट पर शीशे से निर्मित होटल को नोटिस जारी करते हुये नियमानुसार कार्यवाही कराएं। होटल व प्रतिष्ठान संचालकों से कहा कि बुन्देलखण्ड कृषि से सम्बन्धित मिलेट्स उत्पाद (ज्वार, बाजरा, साँवा, रागी, कोदौं आदि) को प्रोत्साहित करें, इससे जनपद के स्थानीय किसानों की आर्थिक आत्मनिर्भरता बढ़ेगी। कहा कि समस्त होटल व्यवसायी अपने मीनू में भी मिलेट्स संबंधी उत्पाद अनिवार्य रूप से शामिल करें। इसके साथ ही एक जनपद एक उत्पाद के अन्तर्गत सभी व्यवसायी अपने रिसेप्शन पर जनपद की बनी हुयी वस्तु रखें। कहा कि समस्त शासकीय कार्यक्रमों में मुख्य अतिथि को उपहार स्वरूप ओडीओपी से सम्बन्धी उत्पाद ही भेंट किये जायेंगें। बताया कि जनपद में आगामी दिवसों में मिलेट्स महोत्सव कार्यक्रम प्रस्तावित है, जिसमें होटल व्यवसायियों के मीनू को लाँच किया जायेगा। सभी होटल व्यवसायी अपने प्रतिष्ठानों में क्यू आर कोड का डिस्प्ले अनिवार्य रूप से प्रदर्शित करें। बताया कि आगामी दिवसों में जनपद में संचालित होटल व्यवसायियों के मध्य स्वच्छता प्रतियोगिता का आयोजन किया जायेगा तथा स्वच्छता मानक को पूर्ण करने वाले प्रथम तीन होटल प्रतिष्ठानों को पुरस्कृत भी किया जायेगा। इस मौके पर सचिव विशेष क्षेत्र प्राधिकरण अजय यादव, कृषि उप निदेशक राजकुमार सहित होटल व्यवसायी आदि मौजूद रहे।

गोवा त्रासदी का असरः दिल्ली में रेस्टोरेंट्स एवं क्लब पर फायर सेफ्टी को लेकर सख्त निगरानी, एडवाइजरी जारी

नई दिल्ली। गोवा में एक नाइट क्लब में आग लगने से 25 लोगों की दर्दनाक मौत के बाद दिल्ली के रेस्तरां संचालकों को एडवाइजरी जारी की गई है। इसमें उन्हें अग्निशमन यंत्रों की जांच व इंतजाम के साथ ही निकासी व प्रवेश के द्वारा अलग-अलग करने जैसे ऐहतियात शामिल हैं। खासकर तब जब क्रिसमस और न्यू ईयर पार्टियों का दौर बस आने वाला ही है। उन दिनों व उसके आस-पास खासकर डिस्को बार व पब में काफी लोग रहते हैं। इसी तरह, कई जगह पार्टियों का आयोजन होता है। नेशनल रेस्टोरेंट एसोसिएशन ऑफ इंडिया (एनआरएआई) के दिल्ली चैप्टर के अध्यक्ष संदीप आनन्द गोयल ने कहा कि यह काफी भयावह दुर्घटना है, जिससे यहां के रेस्तरां संचालकों को भी चिंता में डाला है। उनके अनुसार, वैसे, गोवा की तुलना में दिल्ली में सख्ती अधिक है। यहां बिना अग्निशमन सेवा के एनओसी के रेस्तरां, बार का लाइसेंस नहीं मिलता है। फिर भी उन्हें सचेत रहने को कहा गया है।

क्षेत्रीय युवाओं को एवं बेरोजगारों को जल्द से जल्द रोजगार मुहैया कराए आर.के.टी.सी. कंपनी- देवी सिंह सेंगर

स्वतंत्र प्रभात संवाददाता

शहडोल श्री राजपूत करणी सेना के प्रदेश मंत्री देवी सिंह सेंगर और समस्त पदाधिकारियों ने आर के टी सी बिल्डिंग इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड के जी एम विवेक पाठक से शिष्टाचार भेंट कर इस ई सी एल क्षेत्र से लगे गांवों की समस्या को कंपनी के समक्ष रखा साथ ही बेरोजगार युवाओं को नौकरी देने की बात कही, आपको बता दें कि श्री राजपूत करणी सेना हमेशा से ही क्षेत्र के युवाओं को एवं बेरोजगारों को रोजगार दिलाने के लिए इस ई सी एल कोयलांचल क्षेत्र में काम कर रही समस्त कंपनियों से यह बात कहते आ रहे हैं कि आप हमारे क्षेत्र में हमारी हमारे प्रकृति के भंडारण का व्यवसाय कर रहे हैं जिस कारण से क्षेत्र के लोगों का पहला अधिकार बनता है कि उन्हें रोजगार मुहैया कराया जाए और इस ई सी आर मद से आसपास के गांवो का भी विकास किया जाए।

जन सरोकार की भावना को ध्यान में रखते हुए गरीबों की आजीविका के साधन मुहैया कराना ,स्वच्छता का ध्यान रखना,

मेडिकल संबंधी सहायता प्रदान करना, पर्यावरण नियंत्रण बनाए रखने का प्रयास भी उक्त क्षेत्र में कार्य करने वाली सभी कंपनियों को करना होगा आपको बता दें कि इसके पहले भी एसईसीएल कोयलांचल क्षेत्र में कार्य करने वाली कंपनियों के द्वारा स्थानीय लोगों की एवं बेरोजगारों की अनदेखी करने पर श्री राजपूत करणी सेना के द्वारा वृहद आंदोलन किए गए हैं और काम करने वाली बड़ी-बड़ी कंपनियों को भी इनकी बात मानना पड़ा है। हालांकि आर के टी सी बिल्डिंग इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड के जीएम विवेक पाठक ने हर संभव मदद करने की बात कही है।

शहीद महोत्सव मेला 2025 में झूमी बुंदेली लोक-संध्या, राई नृत्य ने बांधा समां

● सुप्रसिद्ध कलाकारों की धमाकेदार प्रस्तुतियों से महरौनी में गूँजी बुंदेली लोक धुनें

स्वतंत्र प्रभात संवाददाता

महरौनी। अमर शहीद राजेंद्र शुक्ल की स्मृति में आयोजित शहीद महोत्सव मेला 2025 के द्वितीय दिवस पर पारंपरिक लोक संध्या एवं राई नृत्य का भव्य आयोजन किया गया। कार्यक्रम में अतिथियों ने मां सरस्वती तथा शहीद शुक्ल के चित्र पर दीप प्र'वलन एवं फीता काटकर उत्सव का शुभारंभ किया।

कार्यक्रम में बतौर मु य अतिथि उपजिलाधिकारी महरौनी रजनीश कुमार बाजपेई तथा विशिष्ट अतिथि के रूप में कोतवाली प्रभारी निरीक्षक राजा दिनेश सिंह, विवेक प्रकाश सोनी (बंटी भैया), श्रीप्रकाश दुबे (नन्ने महाराज), युवराज सिंह, हकीम सिंह (प्रधान किसरदा), सोनू कुशवाहा सहित अन्य गणमान्यजन उपस्थित रहे। लोक संध्या में बुंदेलखंड के वि यात

कलाकार अरविंद कुशवाहा, राकेश कमाल ठाकुर, रोशनी राजपूत, दीक्षा भारती एंड ग्रुप ने बुंदेलखंड की सांस्कृतिक सुगंध बिखेरते हुए शानदार लोकगीत, राई नृत्य और अन्य पारंपरिक प्रस्तुतियों से दर्शकों को झूमने पर मजबूर कर दिया। राई नृत्य की लय, ताल और ऊर्जा ने उपस्थित जनसमूह का मन मोह लिया।

कार्यक्रम को सफल बनाने में स्मृति समारोह सद्भावना समिति के पदाधिकारियों में ठाकुर धीरज सिंह सिकरवार, प्रदीप पाठक, राजेश श्रीवास्तव, कैलाश नारायण तिवारी, ठाकुर सूर्य प्रताप सिंह, बृजेश रिछारिया, दीपक तिवारी, संजय भौड़ेले, सचिन सोनी, जय हिन्द सिंघई, सतीश सिंघई, सुमित मिठया, पवन पटैरिया, बृजेश नायक, श्रीराम रैकवार, उमेश कुशवाहा, भरत कुशवाहा, राजू पेंटर आदि ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। कार्यक्रम का सफल संचालन पीयूष शुक्ला गोलू द्वारा किया गया।

सुंदर, सुडौल और शक्तिशाली घुटनों के लिए करें जानू शक्ति विकासक क्रिया- रमेश

स्वतंत्र प्रभात संवाददाता

चित्रकूटः जिला मुख्यालय के कुबेर गंज निवासी योगाचार्य रमेश सिंह राजपूत ने पैरों के घुटनों को निरोगी और शक्तिशाली बनाने वाले सूक्ष्म योग जानू शक्ति विकासक क्रिया का अभ्यास कराते हुए बताया कि जानू का मतलब घुटना होता है। बताया कि घुटनों में दर्द होने से चलना-फिरना, उठना-बैठना, चढ़ना-उतरना मुश्किल हो जाता है। जिससे राहत पाने में जानू शक्ति विकासक क्रिया का नियमित अभ्यास करना चाहिए। योगाचार्य ने बताया कि पैर के घुटने तीन मुख्य हड्डियों को मिलाने वाला जोड़ है, जिसमें जांघ की हड्डी (फीमर), पिंडली की हड्डी (टिबिया) तथा पटेला (टोपी), स्नायु बंधन (लिगामेंटस), उपास्थि (कार्टिलेज), टेंडन और मांसपेशियों से एक साथ जुड़ी होती हैं। लिगामेंटस जोड़ को स्थिरता प्रदान करते हैं तथा कार्टिलेज चिकनी फिसलनदार उपास्थि हड्डियों के सिरों को ढकती है, जिससे घर्षण कम होता है और जोड़ को चिकनाई मिलती है। टेंडन और मांसपेशियां घुटनों को गति प्रदान करते हैं। घुटना एक सायनोवियल जोड़ है, जिसमें एक तरल पदार्थ जोड़ को चिकनाई और पोषण देता है। घुटनों में दर्द के अनेक कारण हो सकते हैं। चोट, गठिया और बढ़ती उम्र के साथ बढ़ता शारीरिक वजन। घुटनों के दर्द से मुक्ति पाने के लिए बॉडी वेट नियंत्रण, उचित योग व्यायाम,

पोषण युक्त भोजन और शारीरिक आराम के प्रति जागरूक होना चाहिए। सूक्ष्म योग व्यायाम में जानू शक्ति विकासक योग एक सार्थक और रामबाण उपाय है, जो घुटनों को मजबूती व सुरक्षा देता है। साथ ही जोड़ों के दर्द गठिया में सुधार लाता है। खिलाड़ियों के लिए यह योग बहुत ही उपयोगी है, इसके अभ्यास से घुटने सुंदर, सुडौल और शक्तिशाली बनते हैं। बताया कि इसे करने के लिए साम्यावस्था में खड़े होते हैं तथा श्वास खींचते हुए बाएं पैर की एड़ी को ऊपर उठाकर नितंब से स्पर्श कराते हैं और श्वास छोड़ते हुए पैर को जैसे फुटबॉल में किक मारते हैं ठीक वैसे ही सामने की ओर फेंकते हैं। इसी विधि को दाहिने पैर से भी इसे करते हैं। यह क्रिया 10 बार दोहराते हैं। सावधानी के तौर पर घुटनों में चोट की दशा में चिकित्सक से परामर्श आवश्यक है।

इकलौते बेटे की मौत से परिवार में मातम, बुजुर्ग माता-पिता का छिना बुढ़ापे का सहारा

बाहरी दिल्ली। दिल्ली के रोहिणी में डीटीसी बस ड्राइवर विकास की हत्या के बाद से परिवार में मातम का माहौल है। बुजुर्ग माता-पिता का रो-रोकर बुरा हाल है। किसी को समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर यह कैसे हुआ। हादसे के कुछ देर पहले ही विकास ने अपने परिवार के सदस्यों से फोन पर बात की थी। रविवार को वह अपने परिवार के कुछ सदस्यों से मिलने की बात भी कही थी। विकास के चाचा कृष्ण ने बताया कि वह अपने परिवार का इकलौता बेटा था। विकास अपने पिता अशोक के साथ हरियाणा के बहादुरगढ़ स्थित जसौर खेड़ी गांव में रहता था। परिवार में उसकी एक बहन है, जिसकी शादी हो चुकी है। वह काफी समय से नौकरी की तलाश में था। दो वर्ष पूर्व ही वह डीटीसी में बतौर चालक भर्ती हुआ था। उनकी तैनाती रोहिणी सेक्टर 37 स्थित डिपो में थी। उसके पिता अशोक गांव में खेतीबाड़ी करते हैं। कृष्ण ने बताया कि देर रात उन्हें अस्पताल से विकास के बारे में जानकारी मिली। अस्पताल पहुंचने पर पता चला कि उसकी मौत हो गई। बेटे की मौत के बाद उसके पिता गम में डूब गए हैं। बस एक ही बात कह रहे हैं, विकास ही उनके बुढ़ापे का एक सहारा था। वह भी अब नहीं रहा। पीड़ित परिवार ने मांग की है कि बिना किसी देरी सभी आरोपित पकड़े जाएं, उन्हें सख्त से सख्त सजा मिले, ताकि फिर किसी के साथ ऐसा न हो।

यूपी में निजीकरण के विरोध में एक जनवरी से बिजली कर्मी करेंगे प्रदर्शन, लखनऊ में होगी रैली

स्वतंत्र प्रभात संवाददाता

लखनऊ। विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम, दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम के निजीकरण के विरोध और आंदोलन के बाद किए गए उत्पीड़न की कार्रवाई को समाप्त कराने के लिए एक जनवरी से आंदोलन करेगी। एक से आठ जनवरी तक ड्यूटी के दौरान बिजली कर्मी काली पट्टी बांधेंगे। आठ जनवरी को सभी डिस्काम मुख्यालयों और परियोजनाओं पर विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। 21 जनवरी को लखनऊ में बिजली कर्मियों की रैली होगी।

संघर्ष समिति के संयोजक शैलेंद्र दुबे ने बताया कि रविवार को सभी जिला संयोजक, सह संयोजक, श्रम संघों और सेवा संगठनों के केंद्रीय पदाधिकारियों ने बिजली कर्मियों के उत्पीड़न पर रोष व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि निजीकरण के विरोध के चलते पावर कॉरपोरेशन प्रबंधन ने एक वर्ष में मनमाने ढंग से अल्प वेतन भोगी हजारों संविदा कर्मचारियों को नौकरी से निकाल दिया है।

हजारों बिजली कर्मचारियों का प्रशासनिक आधार पर दूरस्थ स्थानों पर तबादला किया गया है। जिसमें महिला कर्मी भी शामिल हैं। फेशियल अटेंडेंस के नाम पर महीनों तक बिजली कर्मियों का वेतन रोक कर रखा गया है। कार्यालय समय के बाद वीडियो कांफ्रेंसिंग से अलग हटने वाले 87 अधिशासी अभियंताओं को चार्जशीट देकर उनकी पदोन्नति और अन्य देय रोक दिए गए हैं।

यही नहीं बिजली कर्मियों को एक्ट के तहत मिल रही रियायती बिजली की सुविधा समाप्त करने के लिए उनके घरों पर जबरदस्ती स्मार्ट मीटर लगाए जा रहे हैं।

संघर्ष समिति के वरिष्ठ पदाधिकारियों पर आय से अधिक संपत्ति के मामले में झूठी एफआईआर दर्ज की गई हैं।

इन सबके विरोध में आठ जनवरी से ड्यूटी के बाद बिजली कर्मी आपूर्ति के अलावा कोई अन्य कार्य नहीं करेंगे। उपभोक्ताओं और किसानों की समस्याएं प्राथमिकता पर दूर की जाएंगी। सरकार की बिजली बिल राहत योजना में सहयोग किया जाएगा। रैली में बिजली कर्मचारियों, संविदा कर्मियों और अभियंताओं के आंदोलन के अगले कार्यक्रम घोषित किए जाएंगे।